पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

वाराणसी

जनसत्ता

दिनांक-31-06-18

देश को मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने उठाए कई कदम : रविशंकर

वाराणसी, 30 मई (जनसत्ता)।

केंद्रीय विधि और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को मजबूत राष्ट्र बनाने की दिशा में कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं। नोटबंदी के जरिए कालेधन पर अंकुश लगाया गया वहीं दूसरी ओर सर्जिकल स्ट्राइक जैसे साहसिक कदम उठाया गया। रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को डीरेका के सभागार में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि जीएसटी कानून के तहत पूरे देश को एक देश एक कर के दायरे में लाकर आम जनता को परेशानियों से छुटकारा दिलाया है।

प्रधानमंत्री ने चार साल के दौरान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई उपलब्धियों के साथ बदलते भारत की तस्वीर पेश की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत सरकार तीन करोड़ रुपए की धनराशि से बीएचयू

में पूर्वांचल भाषी केंद्र की स्थापना कर रही है जिसमें अवधी, भोजपुरी, मैथिली, मगही में डिजिटल अन्वेषण हो सकेगा। उन्होंने कहा कि वाराणसी में एक महीने के भीतर आयकर अपीलीय न्याधिकरण की स्थापना होगी। वाराणसी में जमीन उपलब्ध होते ही डिजिटल स्टैंडर्ड कोर्ट की स्थापना का रास्ता भी साफ होगा।

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम आयुष्मान भारत की शुरुआत हो गई है जिसके तहत 10 करोड़ परिवार को 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। उड़ान योजना के तहत 25 नए एअरपोर्ट चार साल के भीतर बनकर तैयार हो गई है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि युवा पीढ़ी और किसानों को सशक्त बनाकर ही देश का बेहतर विकास किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पिछले चार सालों में भारत के लिए नया बुनियादी ढांचा तैयार हुआ है जिसका असर विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों के जरिए समाज के विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखने लगा है।

प्रसाद ने कहा कि वित्तीय समावेश के तहत जनधन और जनसुरक्षा योजनाओं ने आम आदमी को सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा प्रदान की है। उन्होंने कहा कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत साल 2022 तक सभी के लिए घर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण विकास और रोजगार व बेहतर स्वास्थ्य के लिए नए-नए कदम उठाए जा रहे हैं।

Scanned by CamScanner

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

वाराणसी

अमर उजाला

दिनांक-31-05-18

काशी में खुलेगा नाइलेट : रविशंकर

आईआईटी बीएचयू में इंक्यूबेशन सेंटर में भोजपुरी पर होगा काम

अमर उजाला ब्यूरो

वाराणसी।

मोदी सरकार के चार साल पूरे होने पर सौगात

एक-डेढ़ महीने में काम शुरू कर देगा टीसीएस का बीपीओ

केंद्रीय विधि एवं न्याय, इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को काशी को कई सौगात दे दीं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (नाइलेट) खोलने की घोषणा के साथ आईआईटी बीएचयू में इंक्यूबेशन सेंटर भी शुरू करने की जानकारी देते हुए मंत्री ने बताया कि इसके लिए 3 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

केंद्र में मोदी सरकार के चार साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बुधवार को यहां पहुंचे प्रसाद ने बताया कि नाइलेट का प्रस्ताव तैयार है। मुख्यमंत्री योगी से बातचीत हो चुकी है। शहर में जगह तलाशी जा रही है। बताया, आईआईटी बीएचयू में भोजपुरी, अवधी, मैथिली, मगही भाषा में अनुवाद करने के लिए सॉफ्टवेयर व प्रोग्रामिंग पर काम हुआ है। वेब वर्जन लांच हो चुका है। इसी पर आगे काम करने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर खोला जा रहा है। इसके बाद पूर्वी यूपी व बिहार की भाषाओं में दुनिया भर से बात की जा सकेगी। बताया कि काशी में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) का बीपीओ अगले एक-डेढ़ महीने में काम शुरू करने लगेगा। प्रथम चरण में 400 लोगों को रोजगार मिलेगा, बाद में 1500 भर्तियां की जाएंगी। उन्होंने गाजीपुर और देवरिया में भी बीपीओ शुरू करने की बात कही।

>> संबंधित पेज 4 पर

Scanned by CamScanner

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार
वाराणसी
अमर उजाला
दिनांक-31-05-18

चार साल में 'ईमानदार भारत' की शुरुआत हुई

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, बिचौलियों के लिए बंद हो गए दिल्ली दरबार के दरवाजे

अमर उजाला ब्यूरो

वाराणसी।

केंद्रीय विधि एवं न्याय, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मोदी सरकार के चार साल के कार्यकाल को ईमानदार भारत की शुरुआत और दुनिया भर में देश का मान बढ़ाने वाला बताया है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व में भारत की बढ़ती साख के कारण पाकिस्तान अलग-थलग पड़ गया है। देश डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया के साथ तकनीकी तौर पर समृद्ध होकर आगे बढ़ रहा है।

बुधवार को डीरेका परिसर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री ने अगले एक वर्ष में 4.5 करोड़ घरों में बिजली पहुंचाने का दावा करते हुए माना कि गंगा को निर्मल और अविरल करने में अभी वक्त लगेगा। गंगोत्री से गंगासागर तक अभियान चलाकर केंद्र सरकार 11500 करोड़ रुपये की 89 परियोजनाओं के जरिए इसके लिए प्रयास कर रही है। 50 करोड़ देशवासियों को पांच-पांच लाख रुपये के बीमा कवर वाली आयुष्मान भारत योजना को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी योजना बताते हुए दावा किया कि मिशन इंद्रधनुष योजना से दवाओं की कीमतें कम हुई हैं। केंद्र सरकार की उपलब्धियों को पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन के साथ प्रसाद ने बताया, 130 करोड़ देशवासियों में से 120 करोड़ आधार कार्ड धारकों को जनधन, मोबाइल और अन्य साधनों से जोड़ा गया है।

गैस-राशन सब्सिडी, मनरेगा, छात्रवृत्ति आदि लाभार्थी के खाते में सीधे जा रही है। इससे बिचौलियों के हिस्से में जाने वाले 90 हजार करोड़ रुपये बचे हैं। अब दिल्ली से जितने रुपये भेजे जाते हैं, लाभार्थी तक पहुंच रहे हैं। स्टार्टअप से उद्यमशीलता बढ़ी है। देश में मोबाइल बनाने वाली 120 फैक्ट्री हैं।

कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में देश को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इसमें सर्जिकल स्ट्राइक जैसा साहसिक कदम है शामिल है ही, नोटबंदी से कालेधन पर अंकुश लगाना भी प्रमुख है। नोटबंदी के दौरान 14-50 लाख करोड़ रुपये वापस आए हैं।

तीन लाख बोगस कंपनियों को बंद कराया गया। जीएसटी से देश को एक कर के दायरे में लाया गया है। आयकर देने वालों की संख्या भी एक करोड़ तक बढ़ गई है।

गंगोत्री से गंगासागर तक गंगा को निर्मल और अविरल करने में अभी समय लगेगा

स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र में आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी योजना

बुधवार को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद।

जिनपिंग-पुतिन ने मोदी का महत्व स्वीकारा

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन के साथ पीएम मोदी के नजदीकी रिश्तों का उल्लेख करते हुए प्रसाद ने बताया कि मध्यपूर्व के देशों में भी भारत के महत्व को स्वीकार कर लिया गया है। बताया, दो बार शी ने प्रोटोकाल तोड़कर मोदी का स्वागत किया है। पुतिन ने 17 साल के कार्यकाल में पीएम मोदी के अलावा किसी राष्ट्राध्यक्ष-शासनाध्यक्ष को हवाई अड्डे तक नहीं छोड़ा है। पीएम इसरायल और फिलिस्तीन जैसे विरोधी देशों को एक साथ साध रहे हैं।

एक महीने में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की बेंच होगी शुरु

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि व्यापारियों की सुविधा और सहूलियत को ध्यान में रखते हुए आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की बेंच एक महीने में यहां व्यवस्थित रूप से शुरू कर दी जाएगी। इसकी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं।

बढ़ रहे हैं धारा 370 खत्म करने की ओर

जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के भाजपा के एजेंडे की प्रगति के बारे में उनका साफ कहना है कि हम इस दिशा में ही आगे बढ़ रहे हैं। एनडीए सरकार की सख्ती के कारण ही अलगाववादी अलग-थलग पड़ गए हैं। आतंकवाद में कमी आई है। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर हमने आतंकवादियों पर कार्रवाई के लिए सुरक्षाबलों को पूरी छूट दे रही हैं। मोदी सरकार देश की सुरक्षा-सम्मान के साथ कोई भी समझौता नहीं करेगी।

सभी के लिए हो एक जैसा कानून

प्रसाद ने कहा, तीन तलाक का मुद्दा धर्म का नहीं है। कुछ रीति-रिवाजों को छोड़ दें तो सभी के लिए एक ही कानून होना चाहिए। विधि आयोग इन पहलुओं पर विचार कर रहा है। यूपी में तीन तलाक से सबसे ज्यादा मामले हैं। एससी-एसटी के हितों के लिए मोदी सरकार ने सख्त कानून बनाया है। बोले बाबा साहब की चिंता की। उन्होंने डॉ. बीआर आंबेडकर, सरदार बल्लभ भाई पटेल और मौलाना अबुल कलाम आजाद को भारत रत्न देने में देरी के लिए कांग्रेस पर सवाल उठाए।

Scanned by CamScanner

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार
वाराणसी
अमर उजाला
दिनांक-31-05-18

आधार को जल्दी ही डीएल से जोड़ेंगे

आधार कार्ड का डेटा सुरक्षित होने का दावा करते हुए प्रसाद ने कहा कि यूपीए के कार्यकाल में आधार कार्ड का कोई मतलब नहीं था। एनडीए सरकार में इसमें दर्ज ब्योरे की निजता को कानूनी संरक्षण दिया गया है। आईटी एक्ट में प्रावधान कर इस डेटा की चोरी करने वाले के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस को भी जल्दी ही आधार से लिंक कर दिया जाएगा। इसके लिए कानूनी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

अयोध्या मामले में हमारा पक्ष मजबूत

कहा, अयोध्या विवाद के मामले में हमारे पास ज्यादा सशक्त साक्ष्य और प्रमाण हैं। अब तक के एएसआई के आधिकारिक दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिए गए हैं। मामले में जल्दी ही फैसला आने की उम्मीद है। आशा है कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को 2019 के लोकसभा चुनाव से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। यह राजनीति का नहीं, आस्था का मामला है। भाजपा विकास और विश्वास की राजनीति करती है।

केंद्रीय विधि-न्याय एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद को सम्मानित करते काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रो. टीएन सिंह।

वेबसाइट को बनाएं क्रिएटिव

वाराणसी। केंद्रीय विधि-न्याय एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को यहां कहा कि विश्वविद्यालय अपनी वेबसाइट को क्रिएटिव बनाएं। उस पर उपलब्धियों, सुविधाओं के साथ अपनी विरासतों का भी जिक्र हो। डिजिटलाइजेशन के दौर में हर कोई एक-दूसरे से जुड़ना चाहता है। लोग जानकारियां चाहते हैं। काशी की क्रिएटिव इमेज वेबसाइट पर मिलनी चाहिए।

विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने दिए सुझाव

बीएचयू, काशी विद्यापीठ और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपतियों के अलावा आईआईटी बीएचयू के निदेशक को केंद्रीय मंत्री ने ये सुझाव दिए। काशी विद्यापीठ कैं समिति कक्ष में 'उच्च शिक्षा के संदर्भ में सूचना एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका' पर आयोजित गोष्ठी में कुलपतियों से मुखातिब मंत्री ने डिजिटल सक्रियता बढ़ाने पर जोर दिया। कहा कि छात्र-छात्राओं और कर्मचारियों-शिक्षकों में डिजिटल इंपावरमेंट लाइए। भारत का मौलिक संविधान मंगाइए, विद्यार्थियों को पढ़ाइए, डिजिटली उसका प्रचार-प्रसार करिए। विश्वविद्यालय की वेबसाइट नियमित तौर पर अपडेट की जाए। बताया कि वह खुद विश्वविद्यालयों की वेबसाइट मॉनिटर करते हैं। उदाहरण के तौर पर काशी विद्यापीठ का जिक्र किया। कहा कि काशी विद्यापीठ में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री पढ़े हैं। स्वाधीनता आंदोलन की यह पवित्र भूमि रही है। इसका उल्लेख वेबसाइट पर होना चाहिए। इस दौरान बीएचयू के कुलपति प्रो. राकेश भटनागर, विद्यापीठ के कुलपति प्रो. टीएन सिंह, संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रो. राजाराम शुक्ल, आईआईटी के निदेशक प्रो. राजीव संगल आदि मौजूद थे। ब्यूरो

Scanned by CamScanner

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार
वाराणसी
द टाइम्स ऑफ़ इंडिया
दिनांक-31-05-18

IIT-BHU incubation centre to promote regional languages

Min Proposes To Establish Modern Court In Varanasi

TIMES NEWS NETWORK

TOI
Union minister Ravi Shankar Prasad was in city

The minister said that the incubation centre will be established at the cost of Rs 3 crore. Besides, for the convenience of income tax lawyers an appellate tribunal would start functioning in the city in a month

Varanasi: The parliamentary constituency of Prime Minister Narendra Modi will soon have an incubation centre for digital research in four regional languages including Bhojpuri, Maithili, Magahi and Awadhi at IIT-BHU.

The union minister for Law and Justice and Electronics and Information Technology Ravi Shankar Prasad announced the establishment of a digital incubation centre at IIT-BHU. He also announced the establishment of an income tax appellate tribunal in Varanasi. He was here on Wednesday to highlight the achievements of four-year-old Modi government.

Talking to reporters, Prasad said that for the digital promotion of the four regional languages of Purvanchal, the incubation centre will be established at the cost of Rs 3 crore. Besides, for the convenience of income tax lawyers an appellate tribunal would start functioning in the city in a month. He said that he also proposes to establish a modern court of international standard in Varanasi. "The work will begin soon after the consent of lawyers and availability of land," he said.

Prasad further said that under the governments BPO promotion scheme a BPO of Tata Consultancy Services would start functioning in Varanasi in a month. Initially the BPO will provide job opportunity to 350-400 youths, but soon its capacity would be expanded further upto 1500, he said adding that so far 91 BPOs have been started in 27 states of the country. The small towns like Deoria and Ghazipur would also be connected with the BPO promotion scheme, he added.

Through power point presentation Prasad highlighted the 4-year achievements of the government in different programmes including infrastructure development, digital India, startup India, women empowerment, surgical strike, demonetization, economic growth, swachhata campaign, health insurance and other welfare schemes for women and poor.

On the issue of triple talaq, Prasad also targeted UPA chairperson Sonia Gandhi, BSP supremo Mayawati and WB chief minister Mamata Banerjee for their silence on triple talaq.

"I do not like to make any political statement on this issue, but I am surprised over their silence on this issue," he said adding that their silence indicated that they do not want the Triple Talaq Bill to get passed.

Scanned by CamScanner

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार
वाराणसी
अमर उजाला
दिनांक-31-05-18

आप लोग जगह तलाशें मॉडल कचहरी हम बनवाएंगे : रविशंकर

वाराणसी। अधिवक्ता साथी जगह तलाशें, मॉडल कचहरी हम बनवाएंगे। बुधवार को सर्किट हाउस में केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यह बात अधिवक्ताओं से कहीं। कहा कि बनारस में डिजिटल और हाइटेक कचहरी परिसर बनाना चाहते हैं और इसके लिए उपयुक्त स्थान अधिवक्ता बताएं। हालांकि कचहरी परिसर अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने की बात सुनकर अधिवक्ता नाखुश दिखे। उनका कहना था कि केंद्रीय मंत्री के दौरे से एक बार फिर कचहरी स्थानांतरण का मुद्दा तूल पकड़ गया है।

कचहरी परिसर को बीते साल पिंडरा क्षेत्र में स्थानांतरित करने की बात शासन स्तर से कही गई थी। साथ ही, इसके लिए बजट भी आवंटित कर दिया गया था। जिला मुख्यालय से कई किलोमीटर दूर कचहरी परिसर स्थानांतरित किए जाने की जानकारी मिलते ही अधिवक्ता आंदोलित हो गए थे। इसके बाद शहर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिवक्ताओं को आश्वस्त किया था कि कचहरी परिसर कहीं अन्यत्र नहीं स्थानांतरित होगा। इस दौरान बनारस बार के अध्यक्ष नरेंद्र श्रीवास्तव, अनूप श्रीवास्तव, नित्यानंद राय, दुर्गा प्रसाद सेठ, प्रवीण मिश्रा, जैकी शुक्ला, अजय बरनवाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। ब्यूरो

अधिवक्ताओं से सर्किट हाउस में मिले केंद्रीय मंत्री

बनारस क्लब के कब्जे वाली जमीन पर क्यों नहीं करते विस्तार

बनारस बार के पूर्व महामंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि बनारस क्लब बेशकीमती सरकारी जमीन पर काबिज है। आखिरकार क्लब के कब्जे वाली सरकारी जमीन पर कचहरी और कलेक्ट्रेट परिसर का विस्तार कर आमजन के हित में काम क्यों नहीं कराया जा रहा है। क्यों जिला मुख्यालय से दूर कचहरी परिसर के स्थानांतरण के बारे में सोचा जा रहा है। नित्यानंद राय ने कहा कि जल्द ही इस संबंध में केंद्रीय कानून मंत्री को पत्र भेजकर बनारस क्लब के कब्जे वाली जमीन पर कचहरी और कलेक्ट्रेट परिसर का विस्तार करने की मांग की जाएगी।

Scanned by CamScanner

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार
वाराणसी
अमर उजाला
दिनांक-31-05-18

आप लोग जगह तलाशें मॉडल कचहरी हम बनवाएंगे : रविशंकर

वाराणसी। अधिवक्ता साथी जगह तलाशें, मॉडल कचहरी हम बनवाएंगे। बुधवार को सर्किट हाउस में केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यह बात अधिवक्ताओं से कहीं। कहा कि बनारस में डिजिटल और हाइटेक कचहरी परिसर बनाना चाहते हैं और इसके लिए उपयुक्त स्थान अधिवक्ता बताएं। हालांकि कचहरी परिसर अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने की बात सुनकर अधिवक्ता नाखुश दिखे। उनका कहना था कि केंद्रीय मंत्री के दौरे से एक बार फिर कचहरी स्थानांतरण का मुद्दा तूल पकड़ गया है।

कचहरी परिसर को बीते साल पिंडरा क्षेत्र में स्थानांतरित करने की बात शासन स्तर से कही गई थी। साथ ही, इसके लिए बजट भी आवंटित कर दिया गया था। जिला मुख्यालय से कई किलोमीटर दूर कचहरी परिसर स्थानांतरित किए जाने की जानकारी मिलते ही अधिवक्ता आंदोलित हो गए थे। इसके बाद शहर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिवक्ताओं को आश्वस्त किया था कि कचहरी परिसर कहीं अन्यत्र नहीं स्थानांतरित होगा। इस दौरान बनारस बार के अध्यक्ष नरेंद्र श्रीवास्तव, अनूप श्रीवास्तव, नित्यानंद राय, दुर्गा प्रसाद सेठ, प्रवीण मिश्रा, जैकी शुक्ला, अजय बरनवाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। ब्यूरो

अधिवक्ताओं से सर्किट हाउस में मिले केंद्रीय मंत्री

बनारस क्लब के कब्जे वाली जमीन पर क्यों नहीं करते विस्तार

बनारस बार के पूर्व महामंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि बनारस क्लब बेशकीमती सरकारी जमीन पर काबिज है। आखिरकार क्लब के कब्जे वाली सरकारी जमीन पर कचहरी और कलेक्ट्रेट परिसर का विस्तार कर आमजन के हित में काम क्यों नहीं कराया जा रहा है। क्यों जिला मुख्यालय से दूर कचहरी परिसर के स्थानांतरण के बारे में सोचा जा रहा है। नित्यानंद राय ने कहा कि जल्द ही इस संबंध में केंद्रीय कानून मंत्री को पत्र भेजकर बनारस क्लब के कब्जे वाली जमीन पर कचहरी और कलेक्ट्रेट परिसर का विस्तार करने की मांग की जाएगी।

Scanned by CamScanner

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

वाराणसी

अमर उजाला

दिनांक-31-05-18

आधार को जल्दी ही डीएल से जोड़ेंगे

आधार कार्ड का डेटा सुरक्षित होने का दावा करते हुए प्रसाद ने कहा कि यूपीए के कार्यकाल में आधार कार्ड का कोई मतलब नहीं था। एनडीए सरकार में इसमें दर्ज ब्योरे की निजता को कानूनी संरक्षण दिया गया है। आईटी एक्ट में प्रावधान कर इस डेटा की चोरी करने वाले के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस को भी जल्दी ही आधार से लिंक कर दिया जाएगा। इसके लिए कानूनी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

अयोध्या मामले में हमारा पक्ष मजबूत

कहा, अयोध्या विवाद के मामले में हमारे पास ज्यादा सशक्त साक्ष्य और प्रमाण हैं। अब तक के एएसआई के आधिकारिक दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिए गए हैं। मामले में जल्दी ही फैसला आने की उम्मीद है। आशा है कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को 2019 के लोकसभा चुनाव से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। यह राजनीति का नहीं, आस्था का मामला है। भाजपा विकास और विश्वास की राजनीति करती है।

केंद्रीय विधि-न्याय एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद को सम्मानित करते काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रो. टीएन सिंह।

वेबसाइट को बनाएं क्रिएटिव

विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने दिए सुझाव

वाराणसी। केंद्रीय विधि-न्याय एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को यहां कहा कि विश्वविद्यालय अपनी वेबसाइट को क्रिएटिव बनाएं। उस पर उपलब्धियों, सुविधाओं के साथ अपनी विरासतों का भी जिक्र हो। डिजिटलाइजेशन के दौर में हर कोई एक-दूसरे से जुड़ना चाहता है। लोग जानकारियां चाहते हैं। काशी की क्रिएटिव इमेज वेबसाइट पर मिलनी चाहिए। बीएचयू, काशी विद्यापीठ और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपतियों के अलावा आईआईटी बीएचयू के निदेशक को केंद्रीय मंत्री ने ये सुझाव दिए। काशी विद्यापीठ कैंपस समिति कक्ष में 'उच्च शिक्षा के संदर्भ में सूचना एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका' पर आयोजित गोष्ठी में कुलपतियों से मुखातिब मंत्री ने डिजिटल सक्रियता बढ़ाने पर जोर दिया। कहा कि छात्र-छात्राओं और कर्मचारियों-शिक्षकों में डिजिटल इंपावरमेंट लाइए। भारत का मौलिक संविधान मंगाइए, विद्यार्थियों को पढ़ाइए, डिजिटली उसका प्रचार प्रसार करिए। विश्वविद्यालय की वेबसाइट नियमित तौर पर अपडेट की जाए। बताया कि वह खुद विश्वविद्यालयों की वेबसाइट मॉनिटर करते हैं। उदाहरण के तौर पर काशी विद्यापीठ का जिक्र किया। कहा कि काशी विद्यापीठ में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री पढ़े हैं। स्वाधीनता आंदोलन की यह पवित्र भूमि रही है। इसका उल्लेख वेबसाइट पर होना चाहिए। इस दौरान बीएचयू के कुलपति प्रो. राकेश भटनागर, विद्यापीठ के कुलपति प्रो. टीएन सिंह, संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रो. राजाराम शुक्ल, आईआईटी के निदेशक प्रो. राजीव संगल आदि मौजूद थे। प्यूरो

Scanned by CamScanner

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

वाराणसी

अमर उजाला

दिनांक-31-05-18

काशी में खुलेगा नाइलेट : रविशंकर

आईआईटी बीएचयू में इंक्यूबेशन सेंटर में भोजपुरी पर होगा काम

अमर उजाला ब्यूरो

वाराणसी।

मोदी सरकार के चार साल पूरे होने पर सौगात

एक-डेढ़ महीने में काम शुरू कर देगा टीसीएस का बीपीओ

केंद्रीय विधि एवं न्याय, इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को काशी को कई सौगात दे दीं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (नाइलेट) खोलने की घोषणा के साथ आईआईटी बीएचयू में इंक्यूबेशन सेंटर भी शुरू करने की जानकारी देते हुए मंत्री ने बताया कि इसके लिए 3 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

केंद्र में मोदी सरकार के चार साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बुधवार को यहां पहुंचे प्रसाद ने बताया कि नाइलेट का प्रस्ताव तैयार है। मुख्यमंत्री योगी से बातचीत हो चुकी है। शहर में जगह तलाशी जा रही है। बताया, आईआईटी बीएचयू में भोजपुरी, अवधी, मैथिली, मगही भाषा में अनुवाद करने के लिए सॉफ्टवेयर व प्रोग्रामिंग पर काम हुआ है। वेब वर्जन लांच हो चुका है। इसी पर आगे काम करने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर खोला जा रहा है। इसके बाद पूर्वी यूपी व बिहार की भाषाओं में दुनिया भर से बात की जा सकेगी। बताया कि काशी में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) का बीपीओ अगले एक-डेढ़ महीने में काम शुरू करने लगेगा। प्रथम चरण में 400 लोगों को रोजगार मिलेगा, बाद में 1500 भर्तियां की जाएंगी। उन्होंने गाजीपुर और देवरिया में भी बीपीओ शुरू करने की बात कही।

>> संबंधित पेज 4 पर

Scanned by CamScanner

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार
वाराणसी
अमर उजाला
दिनांक-31-05-18

चार साल में 'ईमानदार भारत' की शुरुआत हुई

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, बिचौलियों के लिए बंद हो गए दिल्ली दरबार के दरवाजे

अमर उजाला ब्यूरो

वाराणसी।

केंद्रीय विधि एवं न्याय, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मोदी सरकार के चार साल के कार्यकाल को ईमानदार भारत की शुरुआत और दुनिया भर में देश का मान बढ़ाने वाला बताया है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व में भारत की बढ़ती साख के कारण पाकिस्तान अलग-थलग पड़ गया है। देश डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया के साथ तकनीकी तौर पर समृद्ध होकर आगे बढ़ रहा है।

बुधवार को डीरेका परिसर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री ने अगले एक वर्ष में 4.5 करोड़ घरों में बिजली पहुंचाने का दावा करते हुए माना कि गंगा को निर्मल और अविरल करने में अभी वक्त लगेगा। गंगोत्री से गंगासागर तक अभियान चलाकर केंद्र सरकार 11500 करोड़ रुपये की 89 परियोजनाओं के जरिए इसके लिए प्रयास कर रही है। 50 करोड़ देशवासियों को पांच-पांच लाख रुपये के बीमा कवर वाली आयुष्मान भारत योजना को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी योजना बताते हुए दावा किया कि मिशन इंद्रधनुष योजना से दवाओं की कीमतें कम हुई हैं। केंद्र सरकार की उपलब्धियों को पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन के साथ प्रसाद ने बताया, 130 करोड़ देशवासियों में से 120 करोड़ आधार कार्ड धारकों को जनधन, मोबाइल और अन्य साधनों से जोड़ा गया है।

गंगोत्री से गंगासागर तक गंगा को निर्मल और अविरल करने में अभी समय लगेगा

स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र में आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी योजना

गैस-राशन सब्सिडी, मनरेगा, छात्रवृत्ति आदि लाभार्थी के खाते में सीधे जा रही है। इससे बिचौलियों के हिस्से में जाने वाले 90 हजार करोड़ रुपये बचे हैं। अब दिल्ली से जितने रुपये भेजे जाते हैं, लाभार्थी तक पहुंच रहे हैं। स्टार्टअप से उद्यमशीलता बढ़ी है। देश में मोबाइल बनाने वाली 120 फैक्ट्री हैं।

कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में देश को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इसमें सर्जिकल स्ट्राइक जैसा साहसिक कदम है शामिल है ही, नोटबंदी से कालेधन पर अंकुश लगाना भी प्रमुख है। नोटबंदी के दौरान 14-50 लाख करोड़ रुपये वापस आए हैं।

तीन लाख बोगस कंपनियों को बंद कराया गया। जीएसटी से देश को एक कर के दायरे में लाया गया है। आयकर देने वालों की संख्या भी एक करोड़ तक बढ़ गई है।

बुधवार को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद।

जिनपिंग-पुतिन ने मोदी का महत्व स्वीकारा

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन के साथ पीएम मोदी के नजदीकी रिश्तों का उल्लेख करते हुए प्रसाद ने बताया कि मध्यपूर्व के देशों में भी भारत के महत्व को स्वीकार कर लिया गया है। बताया, दो बार शी ने प्रोटोकाल तोड़कर मोदी का स्वागत किया है। पुतिन ने 17 साल के कार्यकाल में पीएम मोदी के अलावा किसी राष्ट्राध्यक्ष-शासनाध्यक्ष को हवाई अड्डे तक नहीं छोड़ा है। पीएम इसरायल और फिलिस्तीन जैसे विरोधी देशों को एक साथ साध रहे हैं।

एक महीने में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की बेंच होगी शुरु

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि व्यापारियों की सुविधा और सहूलियत को ध्यान में रखते हुए आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की बेंच एक महीने में यहां व्यवस्थित रूप से शुरू कर दी जाएगी। इसकी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं।

बढ़ रहे हैं धारा 370 खत्म करने की ओर

जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के भाजपा के एजेंडे की प्रगति के बारे में उनका साफ कहना है कि हम इस दिशा में ही आगे बढ़ रहे हैं। एनडीए सरकार की सख्ती के कारण ही अलगाववादी अलग-थलग पड़ गए हैं। आतंकवाद में कमी आई है। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर हमने आतंकवादियों पर कार्रवाई के लिए सुरक्षाबलों को पूरी छूट दे रखी है। मोदी सरकार देश की सुरक्षा-सम्मान के साथ कोई भी समझौता नहीं करेगी।

सभी के लिए हो एक जैसा कानून

प्रसाद ने कहा, तीन तलाक का मुद्दा धर्म का नहीं है। कुछ रीति-रिवाजों को छोड़ दें तो सभी के लिए एक ही कानून होना चाहिए। विधि आयोग इन पहलुओं पर विचार कर रहा है। यूपी में तीन तलाक से सबसे ज्यादा मामले हैं। एससी-एसटी के हितों के लिए मोदी सरकार ने सख्त कानून बनाया है। बोले बाबा साहब की चिंता की। उन्होंने डॉ. बीआर आंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना अबुल कलाम आजाद को भारत रत्न देने में देरी के लिए कांग्रेस पर सवाल उठाए।

Scanned by CamScanner

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

वाराणसी

दैनिक जागरण

दिनांक-31-05-18

पूर्वांचल को डिजिटल क्षेत्र से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने की पहल, रोजगार के मिलेंगे नए अवसर

काशी में खुलेगी सूचना व प्रौद्योगिकी केंद्र की शाखा

जागरण संवाददाता, वाराणसी : केंद्रीय विधि, न्याय तथा इलेक्ट्रानिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पूर्वांचल को डिजिटल क्षेत्र से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार वाराणसी में राष्ट्रीय सूचना व प्रौद्योगिकी केंद्र (नाइलेट) की शाखा खोलने जा रही है। इससे वाराणसी ही नहीं पूर्वांचल के विभिन्न जिलों के छात्रों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। वहीं पूर्वांचल को डिजिटल इंडिया से जोड़ने में मदद मिलेगी।

वे बुधवार को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में आयोजित 'उच्च शिक्षा के संदर्भ में सूचना एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका' विषयक विमर्श में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। कहा कि नाइलेट सेंटर के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी बात हो गई है। ऐसे में बीएचयू, काशी विद्यापीठ व संस्कृत विश्वविद्यालय सेंटर स्थापित करने के लिए पहल कर सकता हैं। मंत्रालय इसके लिए आर्थिक मदद भी देगा। उन्होंने ई-हेल्थ, ई-स्कालरशिप, ई-रिक्शा का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत सरकार डिजिटल इंडिया की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। कहा कि अब डीएल का फर्जीवाड़ा रोकने के लिए उसे आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। विमर्श में शहर उत्तरी के विधायक रवींद्र जायसवाल, बीएचयू के कुलपति प्रो. राकेश भटनागर, बीएचयू आइआइटी निदेशक प्रो. राजीव संगल, विद्यापीठ के कुलपति प्रो. टीएन सिंह, संविवि के कुलपति प्रो. राजाराम शुक्ल, प्रो. शंभू उपाध्याय, प्रो. चतुर्भुज नाथ तिवारी, प्रो. प्रदीप श्रीवास्तव, प्रो. केंएस जायसवाल, कुलसचिव ओम प्रकाश आदि थे।

काशी विद्यापीठ में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को स्मृतिचिह्न देते कुलपति • जागरण

बोले रविशंकर प्रसाद

- केंद्रीय मंत्री ने बीएचयू, विद्यापीठ व संस्कृत विवि से मांगा प्रस्ताव
- फर्जीवाड़ा रोकने के लिए डीएल को भी आधार से जोड़ने का निर्णय

ये भी कहा केंद्रीय मंत्री ने

- काशी में होगी अंतरराष्ट्रीय स्तर की कचहरी।
- एक माह में इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल की होगी शुरुआत।
- डीजल-पेट्रोल को जीएसटी में लाने पर विचार।
- ग्लोबल लीडर मोदी ने दलालों के लिए बंद किए दिल्ली के दरवाजे।
- डिजिटल इंडिया का सपना हो रहा साकार।
- रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी ही नहीं।
- महिलाओं के सम्मान के मुद्दे पर चुप हैं सोनिया-ममता-माया।

Scanned by CamScanner

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

वाराणसी

आज

दिनांक-31-05-18

वाराणसीमें वीपीओ सेन्टर, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरणकी स्थापना शीघ्र-रविशंकर

केन्द्रीय मंत्री बोले-

सरकार में विचौलियों, दलालों के लिए सभी रास्ते बन्द, पेट्रोल के सेस से मिले धन से होता है विकास कार्य, मूल्य नियन्त्रण के प्रति सरकार गंभीर, गंगा निर्मलीकरण के लिए बन रही दीर्घकालिक नीति, बीएचयू में तीन करोड़ की लागत से खुलेगा पूर्वांचल भाषा केन्द्र, जमीन की उपलब्धता पर 'डिजीटल स्टैंडर्ड कोर्ट शीघ्र'

वाराणसी (का.प्र.)। केन्द्रीय विधि न्याय, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सही नियत सही विकास के नारे के साथ केन्द्र में काम कर रही मोदी सरकार ने चार वर्षो में दलालों और विचौलियों के लिए सभी दरवाजे बन्द कर दिये है। आज अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर भी विकसित राष्ट्र बदलते भारत की ओर देखने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से शीघ्र ही तीन करोड़ की धनराशि से बीएचयू में पूर्वांचल भाषी केन्द्र की स्थापना की जायेगी जिसमें अवधि, भोजपुरी, मैथिली, मगही में डिजिटल अन्वेशण होगा। इसके अलावा एक माह में

(शेष पृष्ठ ९ पर)

Scanned by CamScanner

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

वाराणसी

आज

दिनांक-31-05-18

काशीमें खुलेगा नाइलेटका सेंटर-रविशंकर

काशी विद्यापीठमें विचार व्यक्त करते केन्द्रीय मंत्री रविशंकर·प्रसाद। छाया : आज

केन्द्रीय मंत्री ने कहा छात्रों को डिजिटल क्षेत्र में मिलेगा रोजगार

केंद्र सरकार जल्द ही वाराणसी में नाइलेट (राष्ट्रीय सूचना एवं प्रोद्योगिकी केन्द्र) की एक शाखा खोलेगी। इससे यहां के छात्रों को डिजिटल क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिलेंगे। उक्त बाते बुधवार को काशी विद्यापीठ के पंत प्रशासनिक भवन के डॉक्टर सर्वराधा पल्ली कृष्णनन कक्ष में आयोजित संगोष्ठी में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बतौर मुख्य अतिथि कही। उन्होंने कहा कि काशी के तीन विश्वविद्यालय इसके लिए पहल करें। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय उनकी आर्थिक मदद करेगा। केंद्र सरकार बीएचयू को इनक्यूबेटर सेंटर खोलने के लिए तीन करोड़ का अनुदान देगी। यहां पर भोजपुरी,मैथिली और अवधी भाषाओं को विकसित करने पर काम होगा। इससे पूर्वांचल को डिजिटल इंडिया से जोड़ने में मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर ने बताया कि वाराणसी में महमूरगंज में टीसीएस का सेंटर खुलेगा। पहले चरण में ३०० लोगों को रोजगार मिलेगा। धीरे धीरे इसकी क्षमता बढ़ाई जाएगी। मोबाइल कंपनी की यूनिट भी यहां खुलेगी। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। उन्होंने काशी के विश्वविद्यालयों के वाइसचांसलर से कहा कि वे अपने वेबसाइटों को और समृद्ध करें। सांस्कृतिक विरासत को जोड़े। इससे युवाओं में डिजिटल सक्रियता बढ़ाएं। कार्यक्रम में शहर उत्तरी के विधायक रवींद्र जायसवाल,काशी विद्यापीठ के वाइसचांसलर प्रोफेसर त्रिलोकनाथ सिंह , बीएचयू के वाइसचांसलर प्रोफेसर राकेश भटनागर,बीएचयू आईआईटी के निदेशक प्रोफेसर राजीव संगलए संस्कृत विश्वविद्यालय के वाइसचांसलर प्रोफेसर राजाराम शुक्ल, चीफ प्राक्टर शंभू उपाध्याय, प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह, प्रोफेसर चतुर्भुज नाथ तिवारी, प्रोफेसर केएस जायसवाल, रजिस्टार ओमप्रकाश आदि मौजूद रहे।

Scanned by CamScanner

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

वाराणसी

दैनिक जागरण

दिनांक-31-05-18

कोर्ट के गलियारे से राजनीति कर रही कांग्रेस

जासं, वाराणसी : केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि चुनावों में लगातार मात खा रही कांग्रेस अब कोर्ट के गलियारे से राजनीति करने में जुट गई है। कई मामलों में कांग्रेस ने जनहित याचिका दायर कर केंद्र सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की है। कोलेजियम व्यवस्था की चर्चा करते हुए कानून मंत्री ने सवाल किया कि जजों के चयन में प्रधानमंत्री पर भरोसा क्यों नहीं किया जा सकता है? वह भी तब जबकि तमाम महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर नियुक्ति में प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रविशंकर ने स्पष्ट किया कि उनकी यह राय बतौर कानून मंत्री नहीं है लेकिन जजों के चयन में सरकार की भूमिका पर सवाल उठाया जाना अनुचित है।

विधि, न्याय तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद बुधवार को वाराणसी में थे। डीरेका में मीडिया से बातचीत में कानून मंत्री ने कहा कि मैं एक बार फिर से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कानून मंत्री या मंत्रालय सिर्फ पोस्ट आफिस की तरह कार्य नहीं कर सकता है। यह भी याद दिला दूं कि भाजपा ही थी जो इमरजेंसी के दौर में न्यायपालिका व मीडिया की स्वतंत्रता और नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लड़ी थी।

गंगा निर्मलीकरण को करना होगा थोड़ा इंतजार: रविशंकर प्रसाद ने कहा कि गंगा को लेकर केंद्र सरकार गंभीर है। थोड़ा इंतजार करें गंगा स्वच्छ हो जाएंगी। अभी गंगा की जो हालत है उसके लिए पूर्व की सरकारें जिम्मेदार हैं। मोदी सरकार गंगा सफाई अभियान सिलसिलेवार आगे बढ़ा रही है। गंगोत्री से गंगासागर तक विभिन्न चरणों में सफाई का काम चल रहा है।

बीएचयू में एक्यूबेशन सेंटर: रविशंकर प्रसाद ने बताया कि डिजीटल इंडिया के सपने को साकार करने की दिशा में केंद्र सरकार आइआइटी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक्यूबेशन सेंटर खोलने जा रही है। तीन करोड़ रुपये की लागत से यहां चार भाषाओं भोजपुरी, अवधि, मैथिली और मगही भाषा का डिजीटल अंवेषण होगा। इन भाषाओं को कंप्यूटर फ्रेंडली बनाने की तकनीकी दिक्कतों को भी दूर किया जाएगा ताकि हर व्यक्ति कंप्यूटर का आसानी से अपनी भाषा में इस्तेमाल कर डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ा सके। संबंधित खबरें >>6

बोले कानून मंत्री

- पोस्ट आफिस की तरह कार्य नहीं कर सकता कानून मंत्रालय
- जजों के चयन में सरकार की भूमिका पर सवाल उठाना अनुचित

Scanned by CamScanner

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

वाराणसी

जनवार्ता

दिनांक-31-05-18

बीएचयूः पूर्वांचल भाषी केंद्र की स्थापना शीघ्र

काशी में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने उपलब्धियों का किया बखान, कहा, इससे अवधि, भोजपुरी, मैथिली, मगही में डिजिटल अन्वेषण हो सकेगा

वाराणसी (जनवार्ता समाचार)। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा तीन करोड़ रुपए की धनराशि से बीएचयू में पूर्वांचल भाषी केंद्र की स्थापना की

मोदी के संसदीय क्षेत्र में खुलेगा बीपीओ सेंटर

जाएगी जिसमें अवधि, भोजपुरी, मैथिली, मगही में डिजिटल अन्वेषण हो सकेगा। इसके अलावा वाराणसी में 1 महीने के भीतर आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना होगी। जिससे व्यापारियों को दूसरे जगह जाने से राहत मिलेगी। साथ ही साथ जमीन उपलब्ध होते ही वाराणसी में डिजिटल स्टैंडर्ड कोर्ट की स्थापना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अगले माह में एक बड़ा बीपीओ सेंटर शुरु होगा, जिसमें करीब 1500 लोगों को रोजगार मिलेगा।उन्होंने कहा कि बीपीओ सेंटर एक माह में बनकर तैयार हो जायगा और उसका उद्घाटन

1 महीने के भीतर आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की काशी में होगी स्थापना

प्रधानमंत्री कर सकते हैं।उन्होंने कहा कि शुरु में इस सेंटर पर 350 से 400 लोगों को नौकरी मिलेगी और आने वाले समय में 1500 लोगों को रोजगार मिलेगा। इस केंद्र के खुलने से वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों के सैंकड़ों लोगों, खासकर युवक एवं युवतियों को नौकरी की तलाश में दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में जाने की मजबूरी नहीं रहेगी।श्री प्रसाद ने कहा कि बीपीओ स्थापित करने का वादा खुद उन्होंने वाराणसी वासियों से

डिजिटल स्टैंडर्ड कोर्ट को भी होगा स्थापित

किया था और आज उसके शुरु होने की संभावित समय घोषित करते हुए उन्हें बेहद प्रसन्नता हो रही है। भारत की केंद्र सरकार सही नियत, सही विकास बदलते भारत की तस्वीर के नारे के साथ काम कर रही है। 4 सालों से सरकार ने दलालों और बिचौलियों के लिए सभी दरवाजे बंद कर दिये। यह बातें केंद्रीय विधि ,न्याय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने डीरेका स्थित प्राविधिक प्रशिक्षण केंद्र के सभागार में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। श्री प्रसाद ने कहा कि आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व के समृद्ध और विकसित देश भी बदलते भारत की ओर देखने के लिए मजबूर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल लीडर बनकर उभरे हैं तथा कई देशों ने उन्हे अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। उन्होंने कहां कि प्रधानमंत्री भारत को मजबूत राष्ट्र बनाए जाने की दिशा में अनेक कठोर एवं महत्वपूर्ण निर्णय लिए है। नोटबंदी से लेकर सर्जकल स्ट्राइक तथा जीएसटी जैसे कानूनों पर भी उन्होंने विस्तार से चर्चा की तथा कहा की आम जनता को होने वाली विभिन्न परेशानियों को सरकार समझती है तथा इससे छुटकारा देने के लिए सदा प्रयासरत है। केंद्रीय मंत्री ने केंद्र सरकार के 4 सालों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हुए सरकार द्वारा किसानों, महिलाओ एवं युवाओं हेतु चलाई जा रही योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की जिसमें हेल्थ स्कीम आयुष्मान भारत योजना, स्टार्ट अप इंडिया, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना,जन धन योजना,,जन सुरक्षा योजना ,उज्ज्वला योजना ,स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण प्रधानमंत्री आवास योजना, खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण विकास ,औद्योगिक विकास और रोजगार से जुड़े मुद्दों पर केंद्र सरकार के उपलब्धियां पर विस्तार से चर्चा करते हुए वर्तमान सरकार को हर क्षेत्र में विकास करने हेतु समर्पित एवं सबका साथ सबका विकास को साकार करने वाली सरकार बताया ।पत्रकारवार्ता के पश्चात केंद्रीय मंत्री ने सम्पादकों से भी मुलाकात की। इस दौरन विधायक रविंद्र जायसवाल और भाजपा नेता धर्मेंद्र सिंह भी मौजूद थे।

अब गंगा पर कोई नया बांध नहीं बनेगा

वाराणसी। गंगा की स्वच्छता के सवाल पर केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार गंगा की स्वच्छता हेतु संकल्पित है। 20 हजार करोड़ की लागत वाले परियोजना पर तेज गति से कार्य हो रहे हैं। गंगा किनारे के शहरों एवं गांवों को चिन्हित करके वहां पर एसटीएपी निर्माण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। पूर्ण रूपेण परिणाम आने में थोड़ा वक्त लगेगा। आपने इस बात पर विशेष जोर दिया कि अविरल गंगा एवं निर्मल गंगा हेतु अब गंगा पर कोई नया बांध नहीं बनने देंगे।

Scanned by CamScanner

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

वाराणसी

जनवार्ता

दिनांक-31-05-18

200 करोड़ रूपये में बनेगा अधिवक्ताओं के लिए भवन, परिसरः रविशंकर प्रसाद

केन्द्रीय कानून मंत्री बोले, केन्द्र सरकार में बिचौलियों-दलालों के लिए कोई जगह नही

वाराणसी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि केन्द्र सरकार के दरवाजे दलालों और बिचौलियों के लिए बंद हैं। किसी का कद कुछ भी हो, किसी का पद कुछ भी हो, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। बताया कि विजय माल्या और नीरव मोदी पर

पूरी दुनिया पीएम मोदी की मुरीद

लगातार शिकंजा कस रहा है। एक समान नागरिक संहिता के सवाल पर कहा कि इस पर लॉ कमीशन विचार कर रहा है। लॉ कमीशन इस मुद्दे पर समाज के हर वर्ग से बात करके अपनी राय रिपोर्ट सरकार को देगी। इसके बाद सरकार अन्य राजनीति दलों से इस पर चर्चा करेगी। फिर आगे की कार्यवाही आगे बढ़ेगी। पेट्रोल की कीमतों में लगातार उछाल के सवाल पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में

डीरेका पहुंचने पर केन्द्रीय मंत्री का स्वागत करते अधिकारी।

कच्चे तेल की कीमत में तेजी बताया। कहा कि उनकी सरकार ने पेट्रो पदार्थों के दाम अनियंत्रित किये। बताया कि डीजल और पेट्रोल पर जो सेस लगता है, इससे देश का विकास हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों से पेट्रो पदार्थो के दाम में उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए सरकार दूरगामी नीति बना रही है। बुधवार को काशी पहुंचे केन्द्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दोपहर सर्किट हाउस में अधिवक्ताओं से मुलाकात की। उन्होनें सेंट्रल व बनारस बार से जुड़े पदाधिकारियों व सदस्यों को सम्बोधित करते हुए कहा कि काशी में अधिवक्ताओं के लिए भवन व परिसर बनेगा। इसके लिए सरकार ने 200 करोड़ रूपया स्वीकृत कर दिया है। अधिवक्ता व जिला प्रशासन मिलकर मुख्यालय के निकट स्थान का चयन कर लें, भवन बनना शुरू हो जायेगा। मोदी की शान में कसीदे पढ़ते हुए कानून मंत्री ने कहा कि आज पूरी दुनिया प्रधानमंत्री की मुरीद हो गयी है। कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होनें कहा कि पहले केन्द्र से चला एक रूपया गांव आते-आते 15 पैसा बचता था, अब पूरा का पूरा पैसा सीधे लाभार्थियों के खाते में आने लगा है। इस मौके पर सेंट्रल बार के अध्यक्ष प्रभुनारायण पाण्डेय, महामंत्री संजय सिंह दाढ़ी, बनारस बार के अध्यक्ष नरेन्द्र श्रीवास्तव महामंत्री रजनीश मिश्रा सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद थे।

Scanned by CamScanner

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

वाराणसी

द टाइम्स ऑफ़ इंडिया

दिनांक-31-05-18

IIT-BHU incubation centre to promote regional languages

Min Proposes To Establish Modern Court In Varanasi

TIMES NEWS NETWORK

TOI

Union minister Ravi Shankar Prasad was in city

Varanasi: The parliamentary constituency of Prime Minister Narendra Modi will soon have an incubation centre for digital research in four regional languages including Bhojpuri, Maithili, Magahi and Awadhi at IIT-BHU.

The union minister for Law and Justice and Electronics and Information Technology Ravi Shankar Prasad announced the establishment of a digital incubation centre at IIT-BHU. He also announced the establishment of an income tax appellate tribunal in Varanasi. He was here on Wednesday to highlight the achievements of four-year-old Modi government.

Talking to reporters, Prasad said that for the digital promotion of the four regional languages of Purvanchal, the incubation centre will be established at the cost of Rs 3 crore. Besides, for the convenience of income tax lawyers an appellate tribunal would start functioning in the city in a month. He said that he also proposes to establish a modern court of international standard in Varanasi. "The work will begin soon after the consent of lawyers and availability of land," he said.

The minister said that the incubation centre will be established at the cost of Rs 3 crore. Besides, for the convenience of income tax lawyers an appellate tribunal would start functioning in the city in a month

Prasad further said that under the governments BPO promotion scheme a BPO of Tata Consultancy Services would start functioning in Varanasi in a month. Initially the BPO will provide job opportunity to 350-400 youths, but soon its capacity would be expanded further upto 1500, he said adding that so far 91 BPOs have been started in 27 states of the country. The small towns like Deoria and Ghazipur would also be connected with the BPO promotion scheme, he added.

Through power point presentation Prasad highlighted the 4-year achievements of the government in different programmes including infrastructure development, digital India, startup India, women empowerment, surgical strike, demonetization, economic growth, swachhata campaign, health insurance and other welfare schemes for women and poor.

On the issue of triple talaq, Prasad also targeted UPA chairperson Sonia Gandhi, BSP supremo Mayawati and WB chief minister Mamata Banerjee for their silence on triple talaq.

"I do not like to make any political statement on this issue, but I am surprised over their silence on this issue," he said adding that their silence indicated that they do not want the Triple Talaq Bill to get passed.

Scanned by CamScanner

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

वाराणसी

हिंदुस्तान

दिनांक-31-05-18

बोले केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद- विजय माल्या पर इंग्लैण्ड में कस रहा शिकंजा, नीरव मोदी के करीबियों से पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम के थे रिश्ते

सरकार के दरवाजे दलालों व बिचौलियों के लिए बंद

दो टूक

वाराणसी | कार्यालय संवाददाता

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि दिल्ली सरकार के दरवाजे दलालों और बिचौलियों के लिए बंद हैं। किसी का कद कुछ भी हो, किसी का पद कुछ भी हो, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। बताया कि विजय माल्या और नीरव मोदी पर लगातार शिकंजा कस रहा है।

केंद्रीय विधि, न्याय, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री बुधवार को डीरेका स्थित प्राविधिक प्रशिक्षण केंद्र के सभागार में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। विजय माल्या और नीरव मोदी पर एक सवाल पर उन्होंने यूपीए सरकार में वित्त मंत्री रहे पी. चिदंबरम को घेरा। कहा कि नीरव मोदी को 90 फीसदी लोन पूर्व की सरकार में दिये गये। वर्ष 2012 में नीरव मोदी के रिश्तेदार मेहुल चोकसी का टर्नओवर अचानक तेजी से बढ़ा। बताया कि 26 मई, 2014 को जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, इसके ठीक एक दिन पहले पी. चिदंबरम ने कई नई कंपनियों को भारत में और भारत से एक्सपोर्ट व इंपोर्ट की छूट दे दी। इसमें मेहुल चोकसी की भी कंपनी थी। बताया कि विजय माल्या पर इंग्लैंड में शिकंजा कस रहा है।

पेट्रो कीमतों पर नियंत्रण को सरकार बना रही दूरगामी नीतिः पेट्रोल की कीमतों में लगातार उछाल लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी को बताया। कहा कि उनकी सरकार ने पेट्रो पदार्थों के दाम अनियंत्रित किये। बताया कि डीजल और पेट्रोल पर जो सेस लगता है, इससे देश का विकास हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों से पेट्रो पदार्थों के दाम में उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए सरकार दूरगामी नीति बना रही है।

काशी विद्यापीठ में बुधवार को एक संगोष्ठी के दौरान भाजपा नेताओं से विचार विमर्श करते केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद। ● हिन्दुस्तान

25 मई, 2014 को नीरव मोदी की कंपनी को पूर्व सरकार ने लाभ दिए

01 माह में मिलेगा बनारस को इनकम टैक्स अपीलेंट ट्रिब्यूनल

समान नागरिक संहिता पर विचार कर रहा लॉ कमीशन

समान नागरिक संहिता के सवाल पर कहा कि इस पर लॉ कमीशन विचार कर रहा है। लॉ कमीशन इस मुद्दे पर समाज के हर वर्ग से बात करके अपनी राय (रिपोर्ट) सरकार को देगी। इसके बाद सरकार अन्य राजनीतिक दलों से इस पर चर्चा करेगी। फिर कार्यवाही आगे बढ़ेगी।

गंगा के लिए 11.5 हजार करोड़ की परियोजनाएं

वाराणसी। गंगा निर्मलीकरण के बाबत केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने डीरेका में जानकारी दी कि केंद्र की ओर से कुल 11 हजार पांच सौ करोड़ रुपये की 89 परियोजनाएं चल रही हैं। जैसे-जैसे परियोजनाएं पूरी होंगी, परिणाम दिखने लगेगा। बताया कि कुल 10 शहर ऐसे हैं, जो गंगा को सबसे अधिक प्रदूषित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 89 परियोजनाओं में 49 निर्माणाधीन हैं। 22 टेंडर प्रक्रिया में हैं। जल्द ही इन पर भी काम शुरू होगा। बताया कि 1140 किमी गंगा यूपी में हैं और यहां 4667 करोड़ रुपये से 28 परियोजनाएं मंजूर हैं।

टैक्स अपीलेंट ट्रिब्यूनल

केंद्रीय मंत्री ने घोषणा की कि इनकम टैक्स अपीलेंट ट्रीब्यूनल बनारस में लगेगा। कारोबारियों को इलाहाबाद तक का सफर नहीं तय करना होगा। एक माह में यह सुविधा बनारस में मिलने लगेगी। बहस की सुनवाई यहीं हो सकेगी।

तीन तलाक पर सोनिया, माया, ममता को घेरा

वाराणसी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने डीरेका में सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के दौरान सोनिया गांधी, मायावती और ममता बनर्जी को घेरा। कहा कि महिला होते हुए भी तीन तलाक के मुद्दे पर इनके न बोलने के पीछे वोटबैंक की राजनीति मुख्य कारण है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि तीन तलाक महिलाओं का उत्पीड़न है, ना कि मजहब से जुड़ा मसला। इस मुद्दे पर आज तक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, बसपा अध्यक्ष मायावती और तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी ने कुछ नहीं बोला। ये वोटबैंक की राजनीति करती हैं।

उपलब्धि

ग्लोबल लीडर बनकर उभरे नरेन्द्र मोदी

वाराणसी। मोदी सरकार के चार साल पूरे होने के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को डीरेका के प्राविधिक प्रशिक्षण केंद्र के सभागार में उपलब्धियां गिनाई। आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर हर मामले में मोदी सरकार को यूपीए से बेहतर बताया।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी ताकत के रूप बताया है और वह खुद प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडर बनकर उभरे हैं। इन चार साल में मोदी सरकार ने कई बेहतर कार्य किये। इसमें सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर नोटबंदी पर स्ट्राइक तक है। इसमें तीन लाख फर्जी कंपनियों का पंजीकरण रद हुआ। 35 हजार कंपनियों ने पांच लाख करोड़ जमा किये। उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत रिकॉर्ड शौचालय बनवाये गये। गरीबों के घर बिजली पहुंची। डिजिटलीकरण से लूटखसोट खत्म हुई।

Scanned by CamScanner

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

वाराणसी

हिंदुस्तान

दिनांक-31-05-18

बीएचयू में तीन करोड़ का इनक्यूबेटर सेंटर, महमूरगंज में टीसीएस का केंद्र खोला जाएगा

काशी में खुलेगा नाइलिट का सेंटर : रविशंकर

वाराणसी | वरिष्ठ संवाददाता

केंद्रीय विधि, न्याय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि केंद्र सरकार जल्द ही वाराणसी में नाइलिट (राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान) खोलेगी।

उन्होंने कहा कि काशी में तीन विश्वविद्यालय हैं। वे इसके लिए पहल करें। केंद्र पूरी मदद करेगा। रविशंकर प्रसाद बुधवार को काशी विद्यापीठ में उच्च शिक्षा के संदर्भ में सूचना एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका विषयक संगोष्ठी में मुख्य अतिथि थे।

युवा डिजिटल सक्रियता बढाएं : रविशंकर प्रसाद

वाराणसी। केंद्रीय विधि, न्याय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने युवाओं से कहा कि डिजिटल सक्रियता बढ़ाएं। ब्योरा पेज 04

उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार सूचना प्रौद्योगिकी को हर क्षेत्र में बढ़ावा दे रही है। बीएचयू में इनक्यूबेटर सेंटर खोलने के लिए तीन करोड़ का अनुदान देगी। यहां भोजपुरी, मैथिली व अवधी को विकसित करने पर काम होगा। इससे पूर्वांचल को डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया में शामिल होने में मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि महमूरगंज में टीसीएस का सेंटर खुलेगा। पहले चरण में 300 लोगों को रोजगार मिलेगा। एक मोबाइल कंपनी की यूनिट भी यहां खुलेगी। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। काशी में स्थित विवि के कुलपतियों से उन्होंने कहा कि वे अपने वेबसाइटों को और समृद्ध करें। सांस्कृतिक विरासत को जोड़े। उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे बीएचयू अपने वेबसाइट पर महामना पं. मदन मोहन मालवीय से जुड़ी सामग्री और समृद्धि करे। पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री काशी विद्यापीठ के छात्र थे। उनके बारे में जानकारी काशी विद्यापीठ की वेबसाइट पर होनी चाहिए। नाइलिट खुलने से जिले के प्रशिक्षण केंद्रों को गोरखपुर और दिल्ली नहीं दौड़ना होगा।

Scanned by CamScanner

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

वाराणसी

परफेक्ट मिशन

दिनांक-31-05-18

बीएचयू को इनक्यूबेटर सेंटर खोलने के लिए सरकार देगी तीन करोड़ का अनुदान

काशी में खुलेगी नाइलेट की शाखा : रविशंकर

सौगात

परफेक्ट मिशन/ वाराणसी

केंद्र सरकार जल्द ही वाराणसी में नाइलेट (राष्ट्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी केंद्र) की एक शाखा खोलेगी। इससे यहां के छात्रों को डिजिटल क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिलेंगे। ये बातें केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को प्रेक्षागृह प्राविधिक परीक्षण केन्द्र डीजल रेल इंजन कारखाना, डीएलडब्ल्यू में कहा। उन्होंने कहा कि काशी के तीनों विश्वविद्यालय इसके लिए पहल करें। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय उनकी आर्थिक मदद करेगा। रविशंकर ने बताया कि केंद्र सरकार बीएचयू को इनक्यूबेटर सेंटर खोलने के लिए तीन करोड़ का अनुदान देगी। यहां पर भोजपुरी, मैथिली और अवधी भाषाओं को विकसित करने पर काम होगा। इससे पूर्वांचल को डिजिटल इंडिया से जोड़ने में मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर ने बताया कि काशी में टीसीएस का सेंटर खुलेगा।

- **इनक्यूबेटर सेंटर खोलने के लिए तीन करोड़ का मिलेगा अनुदान**
- **भोजपुरी, मैथिली और अवधी भाषाओं को विकसित करने पर होगा काम**
- **काशी में खुलेगा टीसीएस सेंटर, पहले चरण में मिलेगा 300 लोगों को रोजगार**
- **मोबाइल कंपनी की खुलेगी यूनिट**
- **वकीलों के लिए माडर्न कोर्ट बने जिसके लिए जमीन उपलब्ध कराया जाय**

पहले चरण में 300 लोगों को रोजगार मिलेगा। धीरे-धीरे इसकी क्षमता बढ़ाई जाएगी। मोबाइल कंपनी की यूनिट भी यहां खुलेगी। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। उन्होंने काशी के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से कहा कि वे अपने वेबसाइटों को और समृद्ध करें। उन्होंने कहा युवाओं में डिजिटल सक्रियता बनाएं। श्री प्रसाद ने कहा कि हम चाहते हैं कि वकीलों के लिए एक अच्छा माडर्न कोर्ट बने जिसके लिए जमीन उपलब्ध कराया जाय तो कार्य की शुरूआत की जाय, इसके लिए फण्ड की कोई कमी नहीं होगी।

मोदी सरकार की चार साल की उपलब्धियों का गुणगान करने वाराणसी पहुंचे केन्द्रीय विधि-न्याय, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पेट्रोल मूल्य वृद्धि के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि देखिए भारत की आवश्यकता का 85 प्रतिशत पेट्रोल बाहर से आता है, हमारे यहां पेट्रोल कम होता है। पूर्व केन्द्रीय कोयला मंत्री रह चुके रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हमें बाहर से फ्यूल मंगाना पड़ता है। दुनिया के बाजार में कच्चे तेल की जो स्थिति है इसके दाम का असर भारत में भी पड़ता है। भारत में कच्चे तेल की दुनिया की सबसे टॉप क्लास की रिफाइनरी मौजूद है। पहले की सरकार इसको कंट्रोल करती थी, हमारी सरकार आने के बाद हमने इसे अनियंत्रित किया। जैसे ही दुनिया में रेट डाउन होगा, वैसे ही यहां भी रेट डाउन होगा और जैसे अप होगा वैसे अप होगा। साल भर में आठ से दस बार कीमतें कम हुई हैं, अभी कीमतें बढ़ी हैं ये सच्चाई है।

Scanned by CamScanner

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

वाराणसी

काशीवार्ता

दिनांक-31-05-18

मोदी सरकार में बिचौलियों के रास्ते बंद : रविशंकर प्रसाद

वाराणसी (काशीवार्ता न्यूज)। काशी पहुंचे केन्द्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज दोपहर सर्किट हाउस में अधिवक्ताओं से मिले। उन्होंने

सेण्ट्रल व बनारस बार से जुड़े पदाधिकारियों व सदस्यों को सम्बोधित करते हुए कहा कि वाराणसी में अधिवक्ताओं के लिये विशाल भवन व परिसर बनेगा। इसके लिये सरकार ने पहले ही 200 करोड़ रुपया पास कर दिया है। अधिवक्ता व जिला प्रशासन मिलकर स्थान का चयन कर लें, जो मुख्यालय के निकट हो। उन्होंने सरकार की तमाम योजनाओं की चर्चा करते हुए

अधिवक्ताओं के नये परिसर हेतु 200 करोड़ अवमुक्त

कहा कि भारत तीव्र विकास के शीर्ष पर पहुंचने के लिए तेजी से कदम बढ़ा चुका है। आज पूरी दुनियां प्रधानमंत्री मोदी की मुरीद हो गयी है। इससे भारत की शान भी पहले की अपेक्षा काफी बढ़ी है। भारत में पहले जहां मोबाइल की दो कंपनियां थी अब बढ़कर 102 हो चुकी है। मोदी सरकार ने 7 करोड़ 25 लाख नये शौचालय बनाकर रिकार्ड काम किया है। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि पहले केन्द्र से चला एक रुपया गांव में आते- आते 15 पैसा बचता था अब पूरा का पूरा पैसा सीधे लाभार्थियों के खाते में आने लगा है। बिचौलियों तथा दलालों के सभी रास्ते इस सरकार ने बंद कर दिये हैं। अब भ्रष्टाचार व घूसखोरी करने वाले कदापि बच नहीं सकेंगे। सरकार का शिकंजा और आगे कसता जायेगा। उन्होंने कहा वे बिहार व भुवनेश्वर की यात्रा के बाद काशी आये है, कल हैदराबाद जायेंगे फिर रांची की यात्रा होगी। इस दौरान सेण्ट्रल बार के अध्यक्ष प्रभु नारायण पाण्डेय, महामंत्री संजय सिंह दाढ़ी, बनारस बार के अध्यक्ष नरेन्द्र श्रीवास्तव, महामंत्री रजनीश मिश्रा, एहतेशाम आब्दी, स्वतंत्र सिंह, मनोज त्रिपाठी, मनोज मिश्रा आदि मौजूद रहे।

Scanned by CamScanner

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार
वाराणसी
काशीवार्ता
दिनांक-31-05-18

बनारस को फिर मिले कई तोहफे

वाराणसी (एसएनबी)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस को केन्द्र सरकार के चार साल पूरा होने पर एक बार फिर कई तोहफे मिले। केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने डीरेका में पत्र-प्रतिनिधियों से बातचीत के दौरान इन सौगातों की घोषणा की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का संसदीय क्षेत्र होने के नाते बनारस के लोगों को यह तोहफा देते हुए उन्हें व्यक्तिगत रुप से बड़ी खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग सेक्टर में भारत की दिग्गज कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) का बीपीओ (बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग) खुलेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नालॉजी (नाइलेट) व बीएचयू में इनक्यूबेटर सेंटर खुलेगा जहां पूर्वांचल की अवधी, मैथिली, भोजपुरी भाषा का डिजिटली इनोवेशन का कार्य होगा। केन्द्र सरकार ने इसके लिए तीन करोड़ की राशि भी अवमुक्त कर दी है।

टीसीएस का बीपीओ खुलेगा

नाइलेट व इनक्यूबेटर सेंटर की होगी शुरूआत

सुविधा युक्त न्यायालय का निर्माण होगा

अगले माह आयकर के ट्रिव्यूनल का शुभारंभ

केंद्रीय मंत्री ने बताया, नाइलेट की शाखा खुलने से यहां के छात्रों को डिजिटल क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसके लिए काशी के तीनों विश्वविद्यालय पहल करें। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय उनकी आर्थिक मदद करेगा। बीएचयू में भोजपुरी, मैथिली, मगही व अवधी भाषाओं के डिजिटल अन्वेषण पर काम होगा। इससे पूर्वांचल को डिजिटल इंडिया से जोड़ने में मदद मिलेगी। वाराणसी में टीसीएस का सेंटर अगले एक महीने के अंदर खुलने से पहले चरण में 300 युवाओं को रोजगार मिलेगा। धीरे-धीरे इसकी क्षमता बढ़ाकर 1500 तक की जाएगी। मोबाइल कंपनी की यूनिट भी छह महीने के स्थापित होगी। उन्होंने बनारस के तीनो विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से कहा कि वे अपने वेबसाइटों को और समृद्ध करें तथा युवाओं में डिजिटल सक्रियता बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि बनारस विश्व का सबसे पुराना व जीवन्त शहर है। यह शहर संस्कृति से भी पुरानी है और यहां के सांसद खुद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी है इसलिए भी बनारस के विकास के लिए धन की कहीं कोई कमी नहीं है। बनारस के चारो तरफ राष्ट्रीय राजमार्गो का जाल बिछाया जा रहा है। यह भी कहा कि किसी भी किसान की जमीन जबरन नहीं ली जायेगी न ही घोषित मुआवजा राशि से एक पैसा कम दिया जायेगा।

Scanned by CamScanner

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

वाराणसी

काशीवार्ता

दिनांक-31-05-18

काशी में खुलेगा नाइलेट का सेंटर-रविशंकर प्रसाद

वाराणसी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि केंद्र सरकार जल्द ही वाराणसी में नाइलेट (राष्ट्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी केंद्र) की एक शाखा खुलेगी। इससे यहां के छात्रों को डिजिटल क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि काशी के तीन विश्वविद्यालय इसके लिए पहल करें। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय उनकी आर्थिक मदद करेगा। रविशंकर बुधवार को काशी विद्यापीठ में आयोजित संगोष्ठी में बताया कि केंद्र सरकार बीएचयू को इनक्यूबेटर सेंटर खोलने के लिए तीन करोड़ का अनुदान देगी। यहां पर भोजपुरी, मैथिली और अवधी भाषाओं को विकसित करने पर काम होग। इससे पूर्वांचल को (शेष पृष्ठ 5 पर)

काशी में खुलेगा नाइलेट...

डिजिटल इंडिया से जोड़ने में मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर ने बताया कि वाराणसी में महमूरगंज में टीसीएस का सेंटर खुलेगा। पहले चरण में 300 लोगों को रोजगार मिलेगा। धीरे धीरे इसकी क्षमता बढ़ाई जाएगी। मोबाइल कंपनी की यूनिट भी यहां खुलेगी। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। उन्होंने काशी के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से कहा कि वे अपने वेबसाइटों को औ? समृद्ध करें। सांस्कृतिक विरासत को जोड़े। उन्होंने कहा युवाओं में डिजिटल सक्रियता बढ़ाएं। संगोष्ठी में बीएचयू के कुलपति प्रो.राकेश भटनागर, बीएचयू आईआईटी के निदेशक प्रो.राजीव संगल, संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो.राजाराम शुक्ल, काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रो.टीएन सिंह आदि मौजूद थे।

आतंकी घुसने की...

Scanned by CamScanner

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार
वाराणसी
स्वतंत्र चेतना
दिनांक-31-05-18

बीएचयू में तीन करोड़ की लागत से बनेगा इंक्युबेशन सेंटर-रविशंकर प्रसाद

● कानून मंत्री ने किया घोषणा
● अवधी, मैथिली, भोजपुरी पर होगा काम

चेतना समाचार सेवा

वाराणसी। विधि, न्याय तथा इलेक्ट्रानिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशकर प्रसाद ने कहा कि बीएचयू में तीन करोड़ की लागत से इंक्युबेशन सेंटर खोला जाएगा ताकि भोजपुरी, अवधी,मैथिली भाषा पर काम हो सके।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने काशी में एक सेंटर खोलने का निर्णय लिया है। इस सम्बंध में सीएम से बातचीत हो गई है। जगह की तलाश की जा रही है ताकि इसे जल्द मूर्त रूप दिया जा सके। वह बुधवार को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में आयोजित उच्च शिक्षा के संदर्भ में सूचना एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका विषयक विमर्श में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि टीसीएस बनारस में आ चुकी है। महमूरगंज मे इसे स्थापित किया जा रहा है। प्रथम चरण में तीन सौ लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। जल्द ही पंद्रह सौ की भर्ती होगी। मोबाइल कम्पनी जल्द ही आ रही है। रोजगार से अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने डिजिटल इंडिया के तहत डिजिटल सक्रियता पर बल दिया।

तीनों विश्वविद्यालय के कुलपतियों से कहा कि सबसे पहले अपने विश्वविद्यालयों की वेबसाइट को अपडेट करें। किसी भी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर विरासत का उल्लेख नहीं है। उदाहरण के तौर पर काशी विद्यापीठ में लाल बहादुर शास्त्री पढ़े हैं, स्वाधीनता आदोलन की यह पवित्र भूमि रही है, यहा से बड़े-बड़े नेता जुड़े हैं बावजूद वेबसाइट पर इसका उल्लेख नहीं है। डिजिटल इंडिया में काशी की परंपरिकता दिखे। उन्होंने ई-हेल्थ, ई-स्कालर्शिप, ई-रिक्शा का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत सरकार डिजिटल इंडिया की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। डीएल को आधार कार्ड से जोडेंगे। क्योंकि उंगलिया पहचान नहीं बदल सकती। इस दौरान शहर उत्तरी के विधायक रवींद्र जायसवाल, बीएचयू के कुलपति प्रो राकेश भटनागर, काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रो टीएन सिंह, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो राजाराम शुक्ल, आइआइटी बीएचयू के निदेशक प्रो राजीव संगल, प्रो प्रदीप श्रीवास्तव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

Scanned by CamScanner

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार
वाराणसी
निष्पक्ष समाचार ज्योति
दिनांक-31-05-18

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का अजीबो गरीब बयान, कहा नेशनल हाइवे बन रहे हैं, वहीं मिल रहा लोगों को काम

वाराणसी। रोजगार सृजन पर पीएम नरेंद्र मोदी के पकौड़ा बेचने के बयान के बाद अब केंद्रीय केंद्रीय विधि एवं न्याय और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद बुधवार को वाराणसी में रोजगार सृजन के मसले पर कहा कि नेशनल हाइवे बन रहे हैं, वहीं लोगों को काम मिल रहा है। कहा तीन साल में छह लाख लोगों को आईटी सेक्टर में काम मिला है। मुद्रा योजना में 12 करोड़ 33 लाख लोगों को छह लाख करोड़ रुपये दिए गए। आधे लोगों ने भी एक आदमी को भी जोड़ा तो छह करोड़ को काम मिला न। उन्होंने कहा कि रोजगार काफी बने हैं और बनेंगे। यहां उन्होंने पहले महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में आयोजित संगोष्ठी को संबोधित किया फिर डीरेका में मीडिया को संबोधित करते हुए अजीबो गरीब बयान दिया। उन्होंने काशी विद्यापीठ में आयोजित संगोष्ठी में कहा कि बनारस में जल्द ही राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की एक शाखा खुलेगी। इससे यहां के छात्रों को डिजिटल क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने बीएचयू में तीन करोड़ रुपए से इनक्यूबेशन सेंटर शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से कहा कि वे अपने वेबसाइटों को अपडेट रखें औ? समृद्ध करें। साथ ही सांस्कृतिक विरासत से जोड़ें। केंद्रीय मंत्री रविशंकर ने बताया कि वाराणसी में महमूरगंज में टीसीएस का सेंटर शुरुआत जल्द होगी। पहले चरण में 300 से 400 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके बाद इसकी क्षमता बढ़ाकर 1500 की जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने मोदी सरकार के चार साल की उपलब्धियों का जम कर बखान किया। कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व के समृद्ध और विकसित देशों की सूची में वर्तमान समय में भारत ने अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल करके पूरी दुनिया को बदलते भारत की ओर देखने के लिए मजबूर किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल लीडर बने और कई देशों ने उन्हें अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भारत को मजबूत राष्ट्र बनाये जाने की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये गये है जिसमें जहां एक तरफ नोटबंदी ने कालेधन पर अंकुश लगाया है तो वहीं दूसरी ओर सर्जिकल स्ट्राइक जैसा साहसिक कदम उठा मजबूत संदेश दिया। जीएसटी कानून के तहत पूरे देश को एक देश एक कर के दायरे में लाकर आमजनता को होने वाली विभिन्न परेशानियों

से भी छुटकारा दिलाया है। प्रसाद ने कहा कि भारत सरकार तीन करोड़ रुपए की धनराशि से बीएचयू में पूर्वांचल भाषी केंद्र की स्थापना कर रही है जिसमें अवधी, भोजपुरी, मैथिली, मगही में डिजिटल अन्वेषण हो सकेगा। इसके अलावा वाराणसी में एक महीने के भीतर आयकर अपीलीय न्यायिकरण की स्थापना होगी, जिससे वादकारियों दूसरे जगहों पर जाने से राहत मिलेगी। वाराणसी में जमीन उपलब्ध होते ही डिजिटल स्टैंडर्ड कोर्ट की स्थापना का रास्ता भी साफ होगा। दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम आयुष्मान भारत की शुरुआत हुई है जिससे तहत 10 करोड़ परिवार के 50 करोड़ लोगों को पांच लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा का फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा करें। उड़ान योजना के तहत 25 नए एयरपोर्ट बने है और आमलोगों तक इसकी पहुंच ,सुलभ बनाई जा रही है। केन्द्रीय मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि युवा पीढ़ी और किसानों को सशक्त करके ही देश का बेहतर विकास किया जा राकता है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार के चार वर्ष की उपलब्धियों से आज बदलते भारत की तस्वीर बेहतर तरीके से देखी जा राकती है।

पिछले चार वर्षो में भारत के लिए नया बुनियादी ढांचा विकसित हुआ है जिसका असर विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों के जरिये समाज के विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट दिखाई देने लगा है। श्री प्रसाद ने कहा कि वित्तीय समावेश के अंर्तगत जनधन तथा जनसुरक्षा योजनाओं ने आम आदमी को सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा प्रदान की है तो वही उज्जवला योजना ने करोडों महिलाओं के गरीब परिवारों के लिए धुंआरहित जीवनशैली विकसित की है। स्वच्छ भारत अभियान से रिकार्ड शौचालयों के निर्माण से स्वच्छता की नयी अलख जगाई है, तो वही शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2022तक सभी को घर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। खाद्य सुरक्षा,ग्रामीण विकास और रोजगार व बेहतर स्वास्थ्य के लिए नित्य नये कदम उठाये जा रहे है। विगत चार सालों में दो लाख 42 हजार किलोमीटर आप्टिकल फाइबर बिछाया गया है। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि देश के विकास में युवा शक्ति का बेहतर उपयोग हो सके इसके लिए स्टार्टअप इंडिया द्वारा सभी क्षेत्रों में युवा पीढी को प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों को समृद्ध करके एक राशक्त भारत के सपने को साकार करने का पिछले चार वर्षो में किया गया विकास आज सफलता के नये आयाम स्थापित करके प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सपने सबका साथ सबका विकास को साकार कर रहा है।

Scanned by CamScanner

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

वाराणसी

निष्पक्ष समाचार ज्योति

दिनांक-31-05-18

बीएचयू में तीन करोड़ की लागत से इंक्युबेशन सेंटर

वाराणसी। विधि, न्याय तथा इलेक्ट्रानिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशकर प्रसाद ने कहा कि बीएचयू में तीन करोड़ की लागत से इंक्युबेशन सेंटर खोला जाएगा ताकि भोजपुरी, अवधी, मैथिली भाषा पर काम हो सके। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने काशी में एक सेंटर खोलने का निणय्य लिया है। इस सम्बंध में सीएम से बातचीत हो गई है। जगह की तलाश की जा रही है ताकि इसे जल्द मूर्त रूप दिया जा सके। वह बुधवार को महात्मा गाधी काशी विद्यापीठ में आयोजित 'उच्च शिक्षा के संदर्भ में सूचना एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका' विषयक विमर्श में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे । उन्होंने कहा कि टीसीएस बनारस में आ चुकी है। महमूरगंज मे इसे स्थापित किया जा रहा है। प्रथम चरण में तीन सौ लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। जल्द ही पंद्रह सौ की भर्ती होगी। मोबाइल कम्पनी जल्द ही आ रही है। रोजगार से अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने डिजिटल इंडिया के तहत डिजिटल सक्रियता पर बल दिया। तीनों विश्वविद्यालय के कुलपतियों से कहा कि सबसे पहले अपने विश्वविद्यालयों की वेबसाइट को अपडेट करें। किसी भी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर विरासत का उल्लेख नहीं है। उदाहरण के तौर पर काशी विद्यापीठ में लाल बहादुर शास्त्री पढ़ें है, स्वाधीनता आदोलन की यह पवित्र भूमि रही है, यहा से बड़े बड़े नेता जुड़े है बावजूद वेबसाइट पर इसका उल्लेख नही है। डिजिटल इंडिया में काशी की परंपरिकता दिखे।

Scanned by CamScanner

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार
वाराणसी
जन सन्देश टाइम्स
दिनांक-31-05-18

बीएचयू में भोजपुरी पर होगा डिजिटल शोध

तीन करोड़ की लागत से डिजिटल पूर्वांचल भाषी केंद्र की होगी स्थापना

जनसंदेश न्यूज

वाराणसी। जनपद में एक माह के भीतर आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। इससे न सिर्फ वादकारियों को सहूलियत होगी बल्कि जिले में विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस डिजिटल स्टैंडर्ड कोर्ट स्थापित करने की राह भी आसान होने की उम्मीद है। इस कोर्ट के लिए जमीन तलाशी जा रही है। दूसरी ओर, बीएचयू में अवधी, भोजपुरी, मैथिली, मगही भाषाओं में डिजिटल शोध कार्य के लिए पूर्वांचल भाषी केंद्र आरंभ होगा। इधर, पेट्रो पदार्थों का मूल्य नियंत्रित करने के लिए व्यापक स्तर पर नीति बनाने की तैयारी चल रही है।

बोले रविशंकर प्रसाद

जिले में विश्वस्तरीय डिजिटल स्टैंडर्ड कोर्ट स्थापना के लिए हो रही है जमीन की तलाश

मंत्री ने नरेंद्र मोदी सरकार की चार साल की उपलब्धियों का पेश किया रिपोर्ट कार्ड

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के चार साल की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड पेश करने एकदिनी दौरे पर बुधवार आये केंद्रीय विधि एवं न्याय, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने डीरेका में आयोजित प्रेसवार्ता में यह एलान किया। उन्होंने बताया कि वाराणसी में एक महीने के भीतर आयकर अपीलीय न्याधिकरण की स्थापना हो जाएगी। इस व्यवस्था से वादकारियों को अपने मुकदमों के लिए दूसरे स्थान पर जाने से राहत मिलेगी। वहीं, जनपद में जमीन उपलब्ध होते ही डिजिटल स्टैंडर्ड कोर्ट की स्थापना की तैयारी है। यह न्यायालय विश्व स्तरीय अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा।

इस कोर्ट की स्थापना के लिए केंद्रीय मंत्री ने यहां के जनप्रतिनिधियों संग अधिवक्ताओं की बैठकर कर विचार-विमर्श के बाद **शेष पेज 15 पर...**

डिजिटल सक्रियता बढ़ाने पर जोर दिया

वाराणसी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने तीनों विश्वविद्यालय के कुलपतियों से डिजिटल सक्रियता बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वो अपने विश्वविद्यालय की वेबसाइट अपडेट करें। विश्वविद्यालय के सांस्कृतिक और पारंपरिक पक्षों का उल्लेख वेबसाइट पर होना चाहिए। बुधवार को बनारस में काशी विद्यापीठ के समिति कक्ष में उच्च शिक्षा के संदर्भ में सूचना एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका पर आयोजित गोष्ठी में वो बीएचयू, काशी विद्यापीठ, संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपतियों व आईआईटी बीएचयू के निदेशक से **शेष पेज 15 पर...**

बीएचयू में...

जमीन तलाशने का आह्वान किया। उन्होंने घोषणा की कि बीएचयू में लगभग तीन करोड़ रुपये की लागत से पूर्वांचल भाषी केंद्र की स्थापना हो रही है। इस संस्थान में अवधी, भोजपुरी, मैथिली और मगही भाषाओं को तकनीकी रूप से आगे बढ़ाने की दिशा में डिजिटल अन्वेषण कार्य संभव होगा। एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पेट्रोल-डीजल की दरों में नियंत्रण के लिए सरकार दूरगामी नीति तैयार कर रही है। उन्होंने रोजगार बढ़ने का दावा करते हुए बताया कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की ओर से एक माह के भीतर वाराणसी में बीपीओ सेंटर शुरू हो जाएगा। छोटे-छोटे शहरों में

डिजिटल सक्रियता...

मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि मैं विश्वविद्यालयों की वेबसाइट मॉनीटर करता हूं। आपके विश्वविद्यालय की वेबसाइट ठीक नहीं है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने काशी विद्यापीठ का जिक्र किया। काशी विद्यापीठ में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री पढ़े हैं। स्वाधीनता आंदोलन की वह पवित्र भूमि रही है। कई स्वतंत्रता सेनानी उस दौर में काशी विद्यापीठ और बीएचयू आए। इसका उल्लेख वेबसाइट पर होना चाहिए। वेबसाइट पर विश्वविद्यालय को विरासत का परिचय मिलना चाहिए। हर कोई एक दूसरे से जुड़ना चाहता है, लोग पढ़ना चाहते हैं। काशी की क्रिएटिव इमेज वेबसाइट पर मिलनी चाहिए। ये चीजें एक दूसरे से लोगों को जोड़ती हैं। उन्होंने कुलपतियों से कहा कि आप छात्रों के बीच डिजिटल इंप्रावमेंट लाइए। डिजिटल भारत को पारंपरिक भारत के साथ बदलें। भारत का मौलिक संविधान मंगाइए, विद्यार्थियों को पढ़ाइए, डिजिटली उसका प्रचार प्रसार करिए। ई-हेल्थ, ई-रिक्शा, ई-स्कालरशिप का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत सरकार डिजिटल इंडिया की ओर से तेजी से बढ़ रही है। बताया डीएल को आधार कार्ड से जोड़ने की तैयारी चल रही है क्योंकि नाम बदला जा सकता है, अंगुलियों के निशान नहीं। बीएचयू के कुलपति प्रो. राकेश भटनागर, विद्यालय के कुलपति प्रो. टीएन सिंह, संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रो. राजाराम शुक्ल, आईआईटी के निदेशक प्रो. राजीव संगल समेत वरिष्ठ प्रोफेसर मौजूद रहे।

Scanned by CamScanner

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

वाराणसी

गांडीव

दिनांक-31-05-18

विकास कार्यों में नहीं होगी धन की कमी-रविशंकर प्रसाद

वाराणसी, 30 मई।आज वाराणसी के सर्किट हाउस में रविशंकर प्रसाद संचार मंत्री, भारत सरकार ने अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वाराणसी में जल्द ही अधिवक्ताओं का कोर्ट में मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग बनाया जाएगा और आईटी भवन का निर्माण भी किया जाएगा।उन्होंने कहा कि बनारस में धन की कमी कभी नहीं आएगी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां के सांसद हैं, विकासकार्यों में धन की कमी नहीं होने देंगे। सभा में संयुक्त बार अधिवक्ता समूह, जिलाध्यक्ष शोभनाथ विश्वकर्मा सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे।

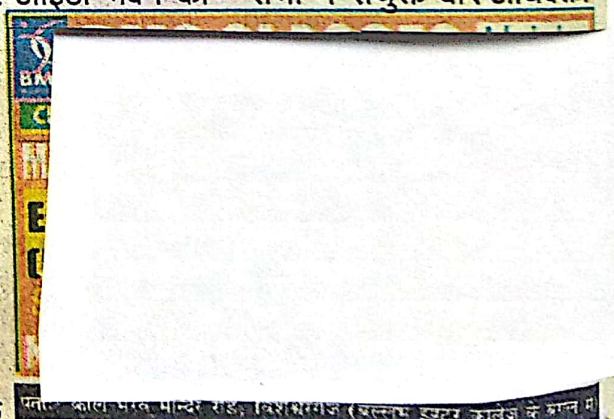

Scanned by CamScanner

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार
वाराणसी
आज
दिनांक-31-05-18

विश्व पटलपर देश आर्थिक ताकतके रूपमें उभरा-रविशंकर

सर्किट हाउसमें केन्द्रीय कानून मंत्रीने अधिवक्ताओंके समक्ष रखी चार वर्षकी उपलब्धि

केन्द्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले चार वर्ष में विश्व पटल पर देश आर्थिक ताकत के रूप में उभर रहा है। डिजिटल इण्डिया के कारण अपनी एक विशेष पहचान बनायी है श्री रविशंकर प्रसाद बुधवार को सर्किट हाउस में अधिवक्ताओं के साथ केन्द्र सरकार के चार वर्ष की उपलब्धियों पर चर्चा कर रहे थे। शहर उत्तरी के विधायक रविन्द्र जायसवाल के संयोजन में हुए अधिवक्ता संवाद कार्यक्रम में श्री रविशंकर प्रसाद ने कहाकि प्रधानमंत्री का उद्देश्य देश के साथ डिजिटली और फिजिकली जुड़े। हम सब लोग फिल्ड में है जनता के बीच में है। दलालों और बिचौलियों के लिए इस सरकार ने दरवाजे बन्द कर रखे है। प्रधानमंत्री के नीतियों के कारण पाकिस्तान अलग-अलग पड़ गया हे चाइना को भी भारत की ताकत का एहसास हुआ है। सबसे ज्यादा पूजी निवेश हुआ है उन्होंने कहाकि १३० करोड़ की आबदी में १२१ करोड़ लोगों के पास स्मार्ट फोन है लोग आधार कार्ड एवं सोशल मीडिया से जुड़े है। देश में १२० मोबाइल फेक्ट्रीयां है। जबकि यूपीए सरकार में मात्र दो मोबाइल निर्माता कम्पनीयां थी। श्री प्रसाद ने कहाकि आयुष्मान भारत योजना के तहत हमारा लक्ष्य ५० करोड़ लोगों को स्वास्थ्य सुविध देना है। उन्होंने अधिवक्ताओं से

कचहरीमें मिलेगी हाईपावर इन्टरनेट सेवा

कहाकि कचहरी को हाईपावर इंटरनेट सुविधा दी जायेगी। कचहरी को देश की सबसे स्मार्ट कचहरी बनाने के लिए आप सब जगह तलाशे सरकार पैसा देगी। कार्यक्रम में विधायक रवीन्द्र जायसवाल के अलावा सेन्ट्रल बार, बनारस बार, कमीशनरी बार, सेल टेक्स बार, इन्कम टेक्स बार के वरिष्ठ पदाधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता उपस्थित थे। जिसमें प्रमुख रूप से रामजनम सिंह, जेपी सिंह, अनुप श्रीवास्तव, नरेन्द्र श्रीवास्तव, विजय शंकर रसतोगी, रोहित मौर्या उपस्थित रहे।

Scanned by CamScanner

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

वाराणसी

स्वतंत्र चेतना

दिनांक-31-05-18

सरकार के दरवाजे दलालों व बिचौलियों के लिए बंद—रविशंकर प्रसाद

● गिनाई चार साल की उपलब्धियां ●पेट्रो कीमतों में नियंत्रण के लिए सरकार बना रही दूरगामी नीति ●एक समान नागरिक संहिता पर विचार कर रहा लॉ कमीशन

वाराणसी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि दिल्ली सरकार के दरवाजे दलालों और बिचौलियों के लिए बंद हैं। किसी का कद कुछ भी हो, किसी का पद कुछ भी हो, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। बताया कि विजय माल्या और नीरव मोदी पर लगातार शिकंजा कस रहा है।

केंद्रीय विधि, न्याय, इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंदी बुधवार को डीरेका स्थित प्राविधिक प्रशिक्षण केंद्र के सभागार में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

विजय माल्या और नीरव मोदी पर एक सवाल पर उन्होंने यूपीए सरकार में वित्त मंत्री रहे पी चिदंबरम को घेरा। कहा कि नीरव मोदी को 90 फीसदी लोन पूर्व की सरकार में दिये गये। वर्ष 2012 में नीरव मोदी के रिश्तेदार मेहुल चोकसी का टर्नओवर अचानक तेजी से बढ़ा। बताया कि 26 मई, 2014 को जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, इसके ठीक एक दिन पहले पी चिदंबरम ने कई नई कंपनियों को भारत में और भारत से एक्सपोर्ट व इंपोर्ट की छूट दे दी। इसमें मेहुल चोकसी की भी कंपनी थी। बताया कि विजय माल्या पर इंग्लैण्ड में शिकंजा कस रहा है।

पेट्रोल की कीमतों में लगातार उछाल के सवाल पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में तेजी बताया। कहा कि उनकी सरकार ने पेट्रो पदार्थों के दाम अनियंत्रित किये। बताया कि डीजल और पेट्रोल पर जो सेस लगता है, इससे देश का विकास हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों से पेट्रो पदार्थों के दाम में उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए सरकार दूरगामी नीति बना रही है।

एक समान नागरिक संहिता के सवाल पर कहा कि इस पर लॉ कमीशन विचार कर रहा है। लॉ कमीशन इस मुद्दे पर समाज के हर वर्ग से बात करके अपनी राय (रिपोर्ट) सरकार को देगी। इसके बाद सरकार अन्य राजनीति दलों से इस पर चर्चा करेगी। फिर आगे की कार्यवाही आगे बढ़ेगी।

Scanned by CamScanner

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार
वाराणसी
आवाज-ए-मुल्क
दिनांक-31-05-18

کام کی بنیاد پر لڑیں گے آئندہ پارلیمانی انتخاب: پرساد

بنارس، ۳۰ مئی۔ چار سالوں کے بعد ہم نے ایماندار بھارت بنایا ہے اور آئندہ مزید ایماندار بنانے کی کوشش جاری ہے۔ مرکز میں نریندر مودی حکومت کے چار سال مکمل ہونے پر ڈیزل ریل انجن کارخانہ کے آڈیٹوریم میں بنارس سے شائع ہونے والے اخبارات کے ایڈیٹروں سے خاص ملاقات میں مرکزی وزیر برائے قانون روی شنکر پرساد نے یہ باتیں کہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک اس وقت ڈیجیٹل انڈیا کی جانب تیزی سے رواں دواں ہے۔ آزادی کے بعد سے 2014 تک یہاں مرکزی حکومتوں نے 6 کروڑ 25 لاکھ بیت الخلاء تعمیر کرایا تھا وہیں صرف چار سال کی ادنیٰ سی مدت میں میں مودی حکومت نے 7 کروڑ سے زائد بیت الخلاء کی تعمیر کروائی ہے۔ اسی طرح منموہن سنگھ حکومت نے جہاں ملک کے اندر صرف دو موبائل کمپنیاں کام کر رہی تھیں آج پی ایم نریندر مودی کے دور میں ہندوستان کے اندر 120 موبائل کمپنیاں کام کر رہی ہیں۔ وزیر موصوف نے پی ایم نریندر مودی کے دور اقتدار میں ہوئے ترقیاتی کاموں کو شمار کراتے ہوئے سابقہ حکومتوں کو جم کر نشانہ بنایا۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم عدالتوں پر یقین رکھتے ہیں اور رام مندر کی تعمیر بھی عدالت کے فیصلہ کے بعد ہی ممکن ہو سکے گی۔ آئندہ پارلیمانی انتخاب میں اس ایجنڈے سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہم آئندہ انتخاب ترقیاتی کاموں کی بنیاد پر لڑیں گے۔

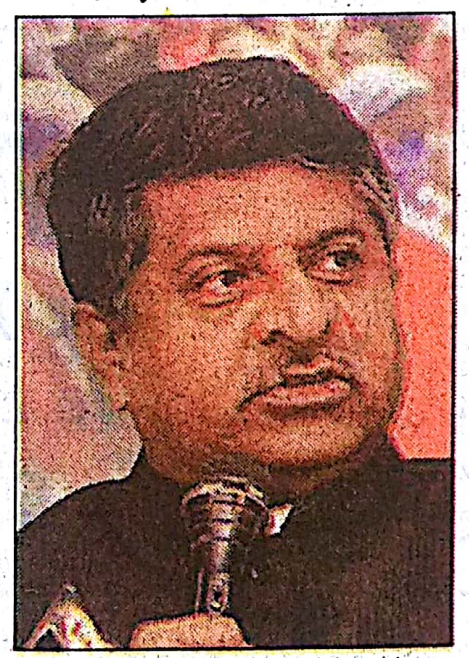

مزید ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہر پارٹی میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بے بنیاد بیانات دیتے رہتے ہیں جس سے کچھ لوگوں کے درمیان خلیج پیدا ہونے لگتی ہے۔ رام مندر مسئلہ کو لے کر پی ایم نریندر مودی، امت شاہ، سشما سوراج، راج ناتھ سنگھ اور میرے ذریعہ کوئی اشتعال انگیز بیانات آئے کیا؟ انہوں نے مزید کہا کہ آستھا اپنی جگہ پر قائم ہے، لہٰذا ملک کی آستھا اور قانون کے دائرہ میں ہی کام ہونا چاہئے۔ مرکزی وزیر نے سپریم کورٹ کے ججوں کی تقرری کے مسئلہ پر کہا کہ پی ایم ایماندار ججوں کی تقرری کیوں نہیں کر سکتا؟ وزیر اعظم عوام کا نمائندہ ہوتا ہے، جب عوام نے انہیں منتخب کر دیا تو ساری ذمہ داریاں بھی وہ بحسن خوبی عوام کے حق میں انجام دیتے ہیں۔ صدر جمہوریہ، نائب صدر جمہوریہ اور الیکشن کمشنر سمیت تمام اہم عہدوں پر تقرریاں پی ایم کے ذریعہ منظور ہو کر آگے بڑھتی ہیں تو پھر جج کی تقرری وزیر اعظم کیوں نہیں کر سکتا، انہوں نے کہا کہ مجھے اس پر سخت اعتراض ہے۔ اور اس معاملہ میں قانون میں ترمیم کی ضرورت ہے۔ گنگا صفائی کے مسئلہ پر وزیر قانون نے کہا کہ اس بارے میں سب سے پہلے ایک حکمت عملی تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ گنگا کی صفائی اور اس میں روانی صرف بنارس شہر میں ہونی چاہئے یا پھر گنگوتری سے لے کر بنگال تک ہونی چاہئے۔ میرے خیال سے گنگا کو صرف بنارس میں نہیں بلکہ ہر مقام پر صاف ستھرا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس میں گندگی بھی صرف بنارس سے نہیں بلکہ 97 شہروں سے ہوتی ہے۔ اس کیلئے بجٹ منظور کیا گیا ہے، اور بڑے پیمانہ پر صفائی مہم جاری ہے۔ اس سلسلہ میں 11 ہزار کروڑ روپے کا پلانٹ لگایا گیا ہے۔ بنارس میں گنگا کو 4667 کروڑ روپے سے صاف کرانے کا پروجیکٹ ہے، جس پر کام جاری ہے۔ خاص ملاقات میں رکن اسمبلی رویندر جیسوال متعدد اخبار کے ایڈیٹر موجود تھے۔

Scanned by CamScanner

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

वाराणसी

राष्ट्रीय सहारा

दिनांक-31-05-18

मुस्लिम बेटियों ने रविशंकर को भेंट की कृति

वाराणसी। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र की मुस्लिम बेटियो ने डिजिटल बुनाई से बनाई गई कृति भेंट की। आईटी मंत्रालय के सहयोग एवं साई इंस्टिट्यूट के द्वारा वाराणसी के लल्लापुरा में स्थापित आईसीटी आधारित संसाधन केंद्र की बेटियो के द्वारा डिजिटल डिजाइन को रेशम के बुनाई से सर्व धर्म समभाव को दर्शाते हुए स्मृति चिन्ह केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को दिया गया।

डीरेका में यह कृति उन्हें रहिमा, तरन्नुम, दीक्षा व दिव्या ने कृति प्रदान की। जन जागरुकता फलक की योजना का प्रारुप भारत कला भवन, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के वरिष्ठ कलाकार डॉ. राधाकृष्ण गणेशन् ने तैयार किया है। सर्वधर्म समभाव शीर्षांकित इस डिजिटल फलक में देश की शान तिरंगा को मुख्य रूप से प्रमुखता दी गयी है जिसमें निहित तीन रंगो के तीन प्रतीकात्मक अर्थ है, नारंगी रंग शौर्य और वीरता का, श्वेत शांति और सद्भाव व हरा हरियाली, समृद्धि, वैभव व सम्पन्नता को दर्शाता है। रविशंकर प्रसाद को दी जाने वाली कृति के बारे में सांई इन्स्टीट्यूट के अगुवा अजय कुमार सिंह बताते हैं कि इस ध्वज पटल की हरी पृष्टभूमि पर गहरे हरे रंग से हिन्दू, मुस्लिम, सिख एवं ईसाई आदि धार्मिक उपासना स्थलों की सपाट छवि है। यानी सभी धर्मो के बीच सामन्जस्यता, सद्भाव एवं एक दूसरे के प्रति समभाव रखने का कृति संदेश दे रही है। इस कृति में उपासना स्थलों के नीचे दो पंक्तियों में आपास में एक दूसरे का हाथ पकड़े, मानव श्रृंखला का चित्रण हमारी अनेकता में एकता या फिर कह लिया जाये प्रधानमंत्री मोदी का सबका साथ सबका विकास को भाव को प्रस्तुत करने में कामयाब है।

Scanned by CamScanner

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार
वाराणसी
आवाज-ए-मुल्क
दिनांक-31-05-18

میٹ ٹو ایڈیٹر کو خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر برائے قانون وانصاف روی شنکر پرساد

حکومت کے دروازے دلالوں اور بچولیوں کے لئے بند: روی شنکر

پروانچل کو ڈیجیٹل انڈیا سے جوڑنے کی ہوگی کوشش

بنارس: مرکزی وزیر روی شنکر پرساد نے کہا کہ دہلی حکومت کے دروازے دلالوں اور بچولیوں کے لئے بند ہیں کسی کا قد کچھ بھی ہو کسی کا عہدہ کچھ بھی ہو ہم اسے چھوڑنے والے نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ وجے مالیا اور نیرو مودی پر لگا تار شکنجہ کستا جارہا ہے مرکزی وزیر کابینہ قانون و انصاف ، الکٹرانک اور انفارمیشن ٹیکنالاجی بدھ کے دن ڈریکا واقع ٹریننگ سینٹر کے ہال میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی مرکزی وزیر روی شنکر پرساد نے کہا ہے کہ مرکزی سرکار جلد ہی وارانسی میں ناٹی لیٹ (نیشنل انفارمیشن اینڈ ٹکنالوجی مرکز) کی ایک برانچ کھولے گی۔ اس سے یہاں کے طلبہ کو ڈیجیٹل شعبہ میں روزگار کے مواقع فراہم ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ کاشی کی تین یونیورسٹیاں اسکے لئے پہل کریں سائنس اور ٹیکنالوجی وزارت انکی مالی مدد کرے گا۔ روی شنکر پرساد بدھ کو کاشی ودیا پیٹھ میں منعقد سیمینار میں بتایا کہ مرکزی حکومت بی ایچ یو انکیو بیٹر سنٹر کھولنے کے لئے تین کروڑ کی گرانٹ دے گی یہاں پر بھوجپوری میتھلی اور اودھی زبانوں کو فروغ دینے پر کام ہوگا۔ اس سے پروانچل کو ڈیجیٹل انڈیا سے جوڑنے میں مدد ملے گی۔

مرکزی وزیر روی شنکر پرساد نے بتایا کہ بنارس میں مہمور گنج میں ٹی سی ایس کا سینٹر کھلے گا پہلے مرحلے میں ۳۰۰ لوگوں کو روزگار ملے گا۔ دھیرے دھیرے اسکی صلاحیت بڑھائی جائے گی۔ موبائل کمپنی کی یونٹ بھی یہاں کھلے گی اس سے مقامی نوجوانوں کو روزگار ملے گا، خاص کر وارانسی اور آس پاس کے علاقوں کے سیکڑوں لوگوں، خاص طور پر نوجوان لڑکے لڑکیوں کو ملازمت کی تلاش میں دہلی، ممبئی جیسے بڑے شہروں میں جانے کی مجبوری نہیں رہے گی، انہوں نے یونیورسٹی کے وائس چانسلروں سے کہا کہ وہ اپنی ویب سائٹوں کو مزید مستحکم کریں۔ ثقافتی وراثت کو جوڑیں انہوں نے کہا کہ نوجوانوں میں ڈیجیٹل سرگرمی بڑھائیں۔ سیمینار میں بی ایچ یو کے وی سی پروفیسر راکیش بھٹناگر، بی ایچ یو آئی آئی ٹی کے ڈائریکٹر پروفیسر راجیو سنگل سنسکرت یونیورسٹی کے وی سی پروفیسر راجہ رام شکلا، کاشی ودیا پیٹھ کے وی سی پروفیسر ٹی این سنگھ وغیرہ موجود تھے۔

ودیاپیٹھ میں ایم اے اردو کا زبانی امتحان ۲/ جون کو

بنارس: مہاتما گاندھی کاشی ودیا پیٹھ میں ایم اے چہارم سمیسٹر ۱۸۔۲۰۱۷ء کا زبانی امتحان ۲/ جون سنیچر کو صبح ۱۰ بجے ہوگا۔

اس بات کی جانکاری دیتے ہوئے شعبۂ اردو کے انچارج ڈاکٹر نظام الدین صاحب نے تمام ریگولر و پرائیویٹ طلبا سے اپیل کی ہے کہ وقت مقررہ پر یونیورسٹی میں حاضر ہو کر زبانی امتحان میں شرکت کریں نیز طلبا اپنا داخلہ امتحان کارڈ ساتھ لائیں۔

Scanned by CamScanner

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार
वाराणसी
राष्ट्रीय सहारा
दिनांक-31-05-18

बिचौलियों के लिए बंद हैं दिल्ली सरकार के दरवाजे : प्रसाद

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

वाराणसी।

केन्द्रीय विधि, न्याय एवं इलेक्ट्रानिक संचार प्रोद्योगिकी मंत्री रविंकर प्रसाद ने केन्द्र की मोदी सरकार की चार साल की उपलब्धियों का लम्बा-चौड़ा खाका प्रस्तुत करते हुए आजादी के बाद पहली बार पिछले चार साल से दिल्ली सरकार के दरवाजे बिचौलिये के लिए बंद कर दिये गये। सरकार ने नीति निर्धारित कर दी गयी है जो होने 'योग्य' होगा वह होकर रहेगा जो होने 'योग्य' नहीं होगा वह किसी भी कीमत पर नहीं होगा चाहे कुछ भी हो जाये।

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की नीति से कुछ विपक्षी दलों को बहुत तकलीफ हो रही है लेकिन हमें उनकी नहीं सवा सौ करोड़ देशवासियों की चिन्ता है। केन्द्रीय मंत्री ने विपक्ष पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि तीन तलाक का मुद्दा न तो पूजा से जुड़ा है न हीं इबादत यह नारी शक्ति के सम्मान से जुड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केन्द्र सरकार संसद में बिल लायी तो वह लोकसभा में पास तो हो गया लेकिन राज्यसभा में भाजपा का बहुमत न होने से यह पास नहीं हो रहा है। विपक्ष की नेता श्रीमती सोनिया गांधी, मायावती तथा मायावती इस मुद्दे पर मौन क्यों धारण

केन्द्रीय मंत्री ने मोदी सरकार की चार साल की उपलब्धियों का ब्योरा पेश किया

किये हुई है।श्री प्रसाद आज डीरेका स्थित प्राविधिक प्रशिक्षण केन्द्र के सभागार में पत्रकारों के सामने मोदी सरकार के चार साल की उपलब्धियों का व्यौरा पेश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश में पहली बार विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति चीन के साथ अनौपचारिक स्तर की बातचीत हुई। पाकिस्तान को आतंकवाद के सवाल पर वैश्विक पटल से किनारे करने में मोदी सरकार सफल हुई। देश के 18 हजार गावों को मिशन मोड में बिजली का कनेक्शन दिया गया। चार साल से सात करोड़ निजी शौचालय का निर्माण कर स्वच्छ भारत-स्वस्थ भारत के परिकल्पना को साकार किया गया। स्वास्थ्य के क्षेत्र पर दस करोड़ परिवारों को पांच-पांच लाख का मेडिकल बीमा केन्द्र सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों को पहले बंदूक न उठाने का निर्देश जारी किया लेकिन यह भी कहा है कि यदि सीमा पार से गोली चले तो उसका मुहतोड़ जवाब देने के लिए किसी आदेश की प्रतीक्षा न करे। केन्द्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि अगले साल तक ग्रोथ रेट 7.5 प्रतिशत तक बढ़ जायेगी। पिछले चार सालों में देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ गयी है। इस अर्थव्यवस्था को कांग्रेस ने बेपटरी कर दिया था अब जब विश्वबाजार में भारतीय अर्थव्यवस्था का डंका बज रहा है तो हमारे कांग्रेसी मित्रों को तकलीफ होना स्वभाविक है। उन्होंने यह भी कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार ने एससी/एसटी एक्ट को मजबूत करने का काम किया है। रोजगार के सवाल पर कहा कि सिर्फ आईटी सेक्टर में पिछले तीन साल में छह लाख लोगों को रोजगार मिला है।

Scanned by CamScanner

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

वाराणसी

ज्ञानशिखा टाइम्स

दिनांक-31-05-18

भोजपुरी के विकास के लिए बीएचयू में खुलेगा इंक्युबेशन सेन्टर-रविशंकर प्रसाद

वाराणसी । विधि, न्याय तथा इलेक्ट्रानिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशकर प्रसाद ने कहा कि बीएचयू में तीन करोड़ की लागत से इंक्युबेशन सेंटर खोला जाएगा ताकि भोजपुरी, अवधी, मैथिली भाषा पर काम हो सके। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने काशी में एक सेंटर खोलने का निर्णय लिया है। इस सम्बंध में सीएम से बातचीत हो गई है। जगह की तलाश की जा रही है ताकि इसे जल्द मूर्त रूप दिया जा सके। वह बुधवार को महात्मा गाधी काशी विद्यापीठ में आयोजित उच्च शिक्षा के संदर्भ में सूचना एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका विषयक विमर्श में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे । उन्होंने कहा कि टीसीएस बनारस में आ चुकी है। महमूरगंज मे इसे स्थापित किया जा रहा है। प्रथम चरण में तीन सौ लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। जल्द ही पंद्रह सौ की भर्ती होगी। मोबाइल कम्पनी जल्द ही आ रही है। रोजगार से

अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने डिजिटल इंडिया के तहत डिजिटल सक्त्रियता पर बल दिया। तीनों विश्वविद्यालय के कुलपतियों से कहा कि सबसे पहले अपने विश्वविद्यालयों की वेबसाइट को अपडेट करें। किसी भी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर विरासत का उल्लेख नहीं है। उदाहरण के तौर पर काशी विद्यापीठ में लाल बहादुर शास्त्री पढ़ें हैं, स्वाधीनता आदोलन की यह पवित्र भूमि रही है, यहा से बड़े बड़े नेता जुड़े हैं बावजूद वेबसाइट पर इसका उल्लेख नहीं है। डिजिटल इंडिया में काशी की परंपरिकता दिखे। उन्होंने ई-हेल्थ, ई-स्कालर्शिप, ई-रिक्शा का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत सरकार डिजिटल इंडिया की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। डीएल को आधार कार्ड से जोड़ेंगे। क्योंकि उंगलिया पहचान नहीं बदल सकती। इस दौरान शहर उत्तरी के विधायक रवींद्र जायसवाल, बीएचयू के कुलपति प्रो राकेश भटनागर, काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रो टीएन सिंह, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो राजाराम शुक्ल, आइआइटी बीएचयू के निदेशक प्रो राजीव संगल, प्रो प्रदीप श्रीवास्तव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

Scanned by CamScanner

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार
वाराणसी
ज्ञानशिखा टाइम्स
दिनांक-31-05-18

पूर्वांचल को तकनीकी रूप से बढ़ाएंगे आगे-रविशंकर प्रसाद

कार्यालय प्रतिनिधि

वाराणसी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व के समृद्ध और विकसित देशों की सूची में वर्तमान समय में भारत ने अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल करके पूरी दुनिया को बदलते भारत की ओर देखने के लिए मजबूर किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल लीडर बने और कई देशों ने उन्हें अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। ये बातें आज बुधवार को वाराणसी के डीरेका सभागार में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए केन्द्रीय विधि एवं न्याय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भारत को मजबूत राष्ट्र बनाये जाने की द्रिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं जिसमें जहां एक तरफ नोटबंदी ने कालेधन पर अंकुश लगाया है तो वहीं दूसरी ओर सर्जिकल स्ट्राइक जैसा साहसिक कदम उठा मजबूत संदेश दिया। जीएसटी कानून के तहत पूरे देश को एक देश एक कर के दायरे में लाकर आमजनता को होने वाली विभिन्न

परेशानियों से भी छुटकारा दिलाया है। इसके अलावा वाराणसी में एक महीने के भीतर आयकर अपीलीय न्याधिकरण की स्थापना होगी, जिससे वादकारियों दूसरे जगहों पर जाने से राहत मिलेगी। वाराणसी में जमीन उपलब्ध होते ही डिजिटल स्टैंडर्ड कोर्ट की स्थापना का रास्ता भी साफ होगा।दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम आयुष्मान भारत की शुरुआत हुई है जिससे तहत 10 करोड़ परिवार के 50 करोड़ लोगों को पांच लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा का फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा करें। उड़ान योजना के तहत 25 नए एयरपोर्ट बने हैं और आमलोगों तक इसकी पहुंच सुलभ बनाई जा रही है।केन्द्रीय मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि युवा पीढ़ी और किसानों को सशक्त करके ही देश का बेहतर विकास किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार के चार वर्ष की उपलब्धियों से आज बदलते भारत की तस्वीर बेहतर तरीके से देखी जा सकती है। पिछले चार वर्षों में भारत के लिए नया बुनियादी ढांचा विकसित हुआ है जिसका असर विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों के जरिये समाज के विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट दिखाई देने लगा है। श्री प्रसाद ने कहा कि वित्तीय समावेश के अर्न्तगत जनधन तथा जनसुरक्षा योजनाओं ने आम आदमी को सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा प्रदान की है तो वही उज्जवला योजना ने करोडों महिलाओं के गरीब परिवारों के लिए धुंआरहित जीवनशैली विकसित की है। स्वच्छ भारत अभियान से रिकार्ड शौचालयों के निर्माण से स्वच्छता की नयी अलख जगाई है, तो वही शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2022 तक सभी को घर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। खाद्य सुरक्षा,ग्रामीण विकास और रोजगार व बेहतर स्वास्थ्य के लिए नित्य नये कदम उठाये जा रहे हैं। विगत चार सालों में दो लाख 42 हजार किलोमीटर आप्टिकल फाइबर बिछाया गया है। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि देश के विकास में युवा शक्ति का बेहतर उपयोग हो सके इसके लिए स्टार्टअप इंडिया द्वारा सभी क्षेत्रों में युवा पीढी को प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों को समृद्ध करके एक सशक्त भारत के सपने को साकार करने का पिछले चार वर्षों में किया गया विकास आज सफलता के नये आयाम स्थापित करके प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सपने 'सबका साथ सबका विकास' को साकार कर रहा है। पत्र सूचना कार्यालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान अपर महानिदेशक, पत्र सूचना कार्यालय, वाराणसी श्री अरिमर्दन सिंह और अपर महानिदेशक, पीएमओ डा.अतुल तिवारी भी मौजूद थे।

Scanned by CamScanner

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

वाराणसी

ज्ञानशिखा टाइम्स

दिनांक-31-05-18

काशी में खुलेगा राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिक का सेंटर- रविशंकर प्रसाद

वाराणसी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि केंद्र सरकार जल्द ही वाराणसी में नाइलेट (राष्ट्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी केंद्र) की एक

शाखा खुलेगी। इससे यहां के छात्रों को डिजिटल क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि काशी के तीन विश्वविद्यालय इसके लिए पहल करें। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय उनकी आर्थिक मदद करेगा। रविशंकर बुधवार को काशी विद्यापीठ में आयोजित संगोष्ठी में बताया कि केंद्र सरकार बीएचयू को इनक्यूबेटर सेंटर खोलने के लिए तीन करोड़ का अनुदान देगी। यहां पर भोजपुरी, मैथिली और अवधी भाषाओं को विकसित करने पर काम होग। इससे पूर्वांचल को डिजिटल इंडिया से जोड़ने में मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर ने बताया कि वाराणसी में महमूरगंज में टीसीएस का सेंटर खुलेगा। पहले चरण में 300 लोगों को रोजगार मिलेगा। धीरे धीरे इसकी क्षमता बढ़ाई जाएगी। मोबाइल कंपनी की यूनिट भी यहां खुलेगी। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। उन्होंने काशी के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से कहा कि वे अपने वेबसाइटों को और समृद्ध करें। सांस्कृतिक विरासत को जोड़े। उन्होंने कहा युवाओं में डिजिटल सक्रियता बढ़ाएं। संगोष्ठी में बीएचयू के कुलपति प्रो.राकेश भटनागर, बीएचयू आईआईटी के निदेशक प्रो.राजीव संगल, संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो.राजाराम शुक्ल, काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रो.टीएन सिंह आदि मौजूद थे।

Scanned by CamScanner

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

वाराणसी

दैनिक मान्यवर

दिनांक-31-05-18

काशी में खुलेगा नाइलेट का सेंटर : रविशंकर प्रसाद

वाराणसी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि केंद्र सरकार जल्द ही वाराणसी में नाइलेट (राष्ट्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी केंद्र) की एक शाखा खुलेगी। इससे यहां के छात्रों को डिजिटल क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि काशी के तीन विश्वविद्यालय इसके लिए पहल करें। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय उनकी आर्थिक मदद करेगा। रविशंकर बुधवार को काशी विद्यापीठ में आयोजित संगोष्ठी में बताया कि केंद्र सरकार बीएचयू को इनक्यूबेटर सेंटर खोलने के लिए तीन करोड़ का अनुदान देगी। यहां पर भोजपुरी, मैथिली और अवधी भाषाओं को विकसित करने पर काम होग। इससे पूर्वांचल को डिजिटल इंडिया से जोड़ने में मदद मिलेगी।

सरकार के दरवाजे दलालों व बिचौलियों के लिए बंद

वाराणसी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि दिल्ली सरकार के दरवाजे दलालों और बिचौलियों के लिए बंद हैं। किसी का कद कुछ भी हो किसी का पद कुछ भी हो हम छोड़ने वाले नहीं हैं।बताया कि विजय माल्या और नीरव मोदी पर लगातार शिकंजा कस रहा है।

केंद्रीय विधि न्याय इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंदी बुधवार को डीरेका स्थित प्राविधिक प्रशिक्षण केंद्र के सभागार में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। विजय माल्या और नीरव मोदी पर एक सवाल पर उन्होंने यूपी सरकार में वित्त मंत्री रहे पी चिदंबरम को घेरा। कहा कि नीरव मोदी को 90 फीसदी लोन पूर्व की सरकार में दिये गये।वर्ष 2012 में नीरव मोदी के रिश्तेदार मेहुल चोकसी का टर्नओवर अचानक तेजी से बढ़ा। बताया कि 26 मईए 2014 को

बोले : रविशंकर

पेट्रो कीमतों में नियंत्रण के लिए सरकार बना रही दूरगामी नीति

ज़ब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इसके ठीक एक दिन पहले पी चिदंबरम ने कई नई कंपनियों को भारत में और भारत से एक्सपोर्ट व इंपोर्ट की छूट दे दी।इसमें मेहुल चोकसी की भी कंपनी थी। बताया कि विजय माल्या पर इंग्लैण्ड में शिकंजा कस रहा है।

पेट्रोल की कीमतों में लगातार उछाल के सवाल पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में तेजी बताया। कहा कि उनकी सरकार ने पेट्रो पदार्थों के दाम अनियंत्रित किये।बताया कि डीजल और पेट्रोल पर जो सेस लगता हैए इससे देश का विकास हो रहा है।अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों से पेट्रो पदार्थों के दाम में उतार.चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए सरकार दूरगामी नीति बना रही है।एक संमान नागरिक संहिता के सवाल पर कहा कि इस पर लॉ कमीशन विचार कर रहा है। लॉ कमीशन इस मुद्दे परं समाज के हर वर्ग से बात करके अपनी राय रिपोर्ट सरकार को देगी। इसके बाद सरकार अन्य राजनीति दलों से इस पर चर्चा करेगी। फिर आगे की कार्यवाही आगे बढ़ेगी।

Scanned by CamScanner